RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 292 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » शनिवार » 23-05-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है : योगी आदित्यनाथ

6 प्रधानमंत्री की अपील समय पूर्व सुरक्षोपाय

7 बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर जाना बेहद मुश्किल काम : रुबीना दिलैक

देश से प्रत्येक घुसपैठिए को ढूंढ निकालेगी सरकार

घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमाओं पर 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना शुरू होगी: शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अगले साल स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा को अभेद्य बनाया जा सके और इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश विफल की जा सके।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा यहां आयोजित वार्षिक रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान में शाह ने इस बात को भी दोहराया कि सरकार देश से प्रत्येक घुसपैठिए को ढूंढ निकालेगी और उन्हें भारत से बाहर भेजेगी।

के.एफ. रुस्तमजी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संस्थापक और पहले महानिदेशक थे। बीएसएफ में लगभग 2.70 लाख जवान हैं और इसे पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी।

शाह ने कहा, भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे बल्कि प्रत्येक घुसपैठिए को ढूंढकर देश से बाहर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दूसरी तरफ से किए जा रहे हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन के प्रयासों के लिए अनुमति नहीं देगी।

शाह ने कहा, मैं बीएसएफ जवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसकी स्थापना के 60वें वर्ष में स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेंगे और पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाओं को अभेद्य बनाएंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के तहत अभेद्य सीमा बनाने में मदद के लिए प्रौद्योगिकी, ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरों का उपयोग किया जाएगा।

शाह ने इन दोनों सीमाओं को असुरक्षित और सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए चिंता का कारण बताते हुए कहा कि इन मोर्चों (पाकिस्तान के साथ लगभग 1,289 किमी और बांग्लादेश के साथ 4,096 किमी) की रक्षा पारंपरिक तरीकों से नहीं की जा सकती है।

मैं गुपचुप तरीके से शादी नहीं करूंगी : कंगना रनौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेत्री-सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वह गुपचुप तरीके से शादी नहीं करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल उस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही, जिसमें वह मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां पहने नजर आ रही हैं।

इस सप्ताह सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आने के बाद रनौत की गुपचुप शादी की अटकलें लगाई जा रही थीं।

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह तस्वीर उनकी आगामी फिल्म के एक किरदार की वेशभूषा में ली गई थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं हर दिन शहर में और उसके आसपास शूटिंग कर रही हूं, किसी ने किरदार के मेकअप में मेरी ये तस्वीर यूं ही खींच ली और अब मुझे ढेरों फोन आ रहे हैं।

रनौत ने कहा कि एक अभिनेत्री के तौर पर उन्हें अलग-अलग तरह के किरदार निभाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा, शादीशुदा महिला के किरदार में क्या बड़ी बात है? अदाकार हर तरह के किरदार निभाते हैं, मैं छुपकर शादी नहीं करूंगी, वादा करती हूं।

अभिनेत्री इस समय कई फिल्मों पर काम कर रही हैं। वह 12 जून को रिलीज होने वाली फिल्म भारत भाग्य विधाता में नजर आएंगी।

पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों और मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य: दिलीप घोष

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भर के सभी स्कूलों और मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान 'वंदे मातरम' गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय का यह आदेश राज्य की भाजपा सरकार द्वारा सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पत्रकारों से कहा, वंदे मातरम सभी स्कूलों और मदरसों में, हर जगह गाया जाएगा। जहां भी सरकारी निधि का उपयोग होता है और सरकारी कानून लागू होते हैं वहां राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए। पूरे देश में इसी तरह इसका पालन किया जाता है। 'ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन' के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि मदरसे इस आदेश को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। कबीर ने कहा, '' मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरकार को मदरसों में ऐसे मामलों पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है।'' उन्होंने दावा किया कि अगर यह निर्देश लागू किया गया, तो ''सभी मुसलमान एकजुट होकर इस फरमान का विरोध करेंगे।''

फर्स्ट टेक

कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा : डब्ल्यूएचओ प्रमुख

जिनेवा/एपी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख के मुताबिक अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का प्रकोप 'तेजी से बढ़ रहा है' और राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति 'विकराल' हो रही है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कांगो के भीतर जोखिम के अपने आकलन को संशोधित किया है और अब यह ''बहुत उच्च'' श्रेणी में है, जिसे पहले 'उच्च' श्रेणी में माना गया था। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि क्षेत्रीय स्तर पर इबोला संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है, लेकिन फिलहाल इसके वैश्विक महामारी में तब्दील होने की आशंका कम है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने बताया कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 82 मामलों और इस बीमारी के कारण सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, ''लेकिन हम जानते हैं कि कांगो में महामारी का प्रकोप कहीं अधिक व्यापक है।''

भारत के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का पूर्वानुमान : आईएमडी

नई दिल्ली/भाषा। उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अगले छह से सात दिनों के दौरान लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने कहा कि 22 से 28 मई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया, इसी अवधि के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भीषण लू चलने का अनुमान है। आईएमडी ने 22 से 28 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलने की प्रबल संभावना जताई है। इन क्षेत्रों के कुछ इलाकों में 24 से 27 मई के बीच भीषण लू की स्थिति हो सकती है।

नालंदा जिले में 10 वर्ष पुराने पुल के कई पिलर ढहे

नालंदा (बिहार)/भाषा। बिहार के नालंदा जिले में दरियापुर स्थित सकरी नदी पर बने एक पुल के कई पिलर शुक्रवार को ढह गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस पुल के कई पिलर सोमवार को भी क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गए थे। करीब 10 वर्ष पहले निर्मित यह पुल नालंदा जिले के पूर्वी हिस्से को शेखपुरा जिले के पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम घटना की जांच कर रही है।

सूर्यास्त 23-05-2026 6:40 बजे	सूर्योदय 24-05-2026 5:52 बजे
BSE 75,415.35 (+231.99)	NSE 23,719.30 (+64.60)
सोना 16,417 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 278,564 रु. प्रति किलो

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का त्रुटिरहित आयोजन कराना है लक्ष्य : प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के आयोजन में अनियमितताएं सामने आने के बाद सरकार को ''कड़े फैसले'' लेने पड़े और प्राधिकारी यह नहीं चाहते कि ''परीक्षा माफिया'' के कारण किसी भी योग्य अभ्यर्थी को उसके हक की सीट से वंचित होना पड़े।

प्रधान ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 21 जून को पुन: होने वाली परीक्षा ''शत प्रतिशत त्रुटिरहित'' रहे।

उन्होंने 'जागरण भारत एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा से जुड़े विवाद के कारण करीब 22 लाख विद्यार्थियों को ''मानसिक पीड़ा'' सहनी पड़ी और सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ''22 लाख बच्चों को भारी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उस पीड़ा को समझते हुए और जिम्मेदारी लेते हुए मैं आज कह रहा हूं कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े।''

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तीन मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने हाल में रद्द कर दिया था। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है और दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है।

प्रधान ने कहा कि सरकार ने यह पता लगने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला किया कि ''कुछ मूल्यांकनों में गड़बड़ी हुई थी।''

पाकिस्तान के लोग अंततः भारत में अपनी पैतृक जड़ों की ओर लौटेंगे : सत्येंद्र सिंह

नई दिल्ली/भाषा। वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने संभावनाओं के दरवाजे खुले रखने की वकालत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग अंततः अपने इतिहास को समझेंगे और भारत में अपने 'पूर्वजों की जड़ों और परंपराओं' की ओर लौटेंगे। सिंह ने आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले की इस टिप्पणी का भी समर्थन किया कि पाकिस्तान के साथ गतिरोध को तोड़ने के लिए लोगों से लोगों का संपर्क महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमेशा एक अवसर होना चाहिए क्योंकि पड़ोसी देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में अब कोई विश्वास नहीं बचा है।

'पीटीआई वीडियो' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सिंह ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान को स्वतंत्रता के बाद भारत से अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाया गया था लेकिन वहां रहने वाले लोगों की जड़ें अब भी भारत में हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद जीती

हार के बावजूद आरसीबी तालिका में शीर्ष पर रही

हैदराबाद/भाषा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुकवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में 55 रन से जीत हासिल की लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से नहीं रोक सकी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा (56 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी, ईशान किशन (79 रन) के बेखौफ अंदाज और हेनरिक क्लासेन (51 रन) की ताकतवर हिटिंग की बदौलत चार विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। आरसीबी को शीर्ष दो में रहने के लिए 166 रन का स्कोर बनाना था और 178 रन से ज्यादा रन का स्कोर बनाने से उसका शीर्ष स्थान तय था।

राज्यसभा की 24 सीट के लिए 18 जून को चुनाव कराएगा निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली/भाषा। निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे एवं दिग्विजय सिंह समेत राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल आगामी दो महीने में समाप्त होने के मद्देनजर उच्च सदन की 24 सीट के लिए 18 जून को चुनाव कराने की शुक्रवार को घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव उन 10 राज्यों में होंगे जहां मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है।

भारत और साइप्रस ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ शुक्रवार को व्यापक बातचीत की तथा इस दौरान भारत एवं साइप्रस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला और बुनियादी ढांचे एवं नौवहन जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित किया।

दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट और यूक्रेन संघर्ष पर भी विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शत्रुता को जल्द समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

मोदी ने मीडिया में जारी बयान में कहा, ''पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है। दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से अनेक नई संभावनाएं सामने आई हैं।'' उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने इसका लाभ उठाते हुए अगले पांच वर्ष में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

हाजिर हो

जनप्रतिनिधि का दायित्व यही,
कर्तव्यों पर वे रहे स्थित।
बहुमूल्य वोट देकर उनको,
हमने चाहा जन-जन का हित।
संसद है पूजा स्थल उनका,
जब खुले रहे तब हाजिर नित।
वर्ना पूछेगी जनता अब,
क्यों रहे सदन से अनुपस्थित।।

कैग की ओर से ऑडिट के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समय की मांग : वेणुगोपाल

नई दिल्ली/भाषा। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के प्रमुख केसी वेणुगोपाल ने 'ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम' के तहत विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष बड़े पैमाने पर कार्यवाही नोट लंबित होने को लेकर शुक्रवार को चिंता जताई और कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से ऑडिट के लिए अधिक सहयोगात्मक और त्वरित प्रतिक्रिया समय की मांग है। उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए गठित पीएसी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भाजपा की अपराजिता सारंगी और सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव तथा समिति के कई अन्य सदस्य शामिल हुए।

बैठक के बाद कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''लोक लेखा समिति (2026-27) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। पिछली पीएसी (2025-26) ने संसद में 26 रपट सफलतापूर्वक प्रस्तुत कीं। ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम में भारी बैकलॉग गंभीर चिंता का कारण है, जिसमें 1500 से अधिक 'एक्शन टेकन नोट' (एटीएन) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समक्ष लंबित हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे देश में सार्वजनिक व्यय की जटिल प्रकृति को देखते हुए कैग की ओर से ऑडिट के लिए अधिक सहयोगात्मक और त्वरित प्रतिक्रिया समय की मांग है। 'ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम' एक डिजिटल मंच है, जिसे सरकारी ऑडिट से संबंधित आपत्तियों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रपटों के समाधान के लिए विकसित किया गया है।

ठाणे में मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़, 34.18 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

ठाणे/भाषा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की कल्याण पुलिस ने मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए शुक्रवार को बताया कि उसने लगभग 34.18 करोड़ रुपए मूल्य की 9.7 किग्रा हेरोइन बरामद की है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में एक कुख्यात अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता भी शामिल है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय जाधव ने बताया कि कल्याण की 'एंटी-नार्कोटिक्स एक्शन टीम' ने इस ऑपरेशन के दौरान कई छापेमारी की और यह सिलसिला कई सप्ताह चला।

पुलिस के अनुसार, एक अप्रैल को उपनिरीक्षक अनिल गायकवाड़ के नेतृत्व में एक टीम ने शाहपुर निवासी कासिम अब्दुल सत्तार वसईकर (38) और कृष्ण नागप्पा हलेमानी (36) को सांगलेवाड़ी मार्ग पर रोका। उनके पीठ पर लादने वाले बैग की तलाशी में 9.2 किग्रा हेरोइन और नकदी बरामद हुई।

त्विषा शर्मा की मौत के मामले में पति समर्थ सिंह को जबलपुर में हिरासत में लिया गया

जबलपुर (मप्र)/भाषा। दहेज के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित की गई और भोपाल में अपने ससुराल में पिछले सप्ताह मृत पाई गई त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को शुक्रवार शाम यहां पुलिस ने जिला अदालत परिसर से हिरासत में ले लिया। समर्थ के वकील जयदीप कौरव ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उनके मुवक्किल जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे लेकिन जबलपुर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर ओमती थाने ले गई, जहां उन्हें भोपाल पुलिस को सौंपा जाएगा।

इससे पहले, जबलपुर जिला अदालत परिसर में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। समर्थ के जिला न्यायालय पहुंचने की खबर मिलते ही दर्जनों पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर अदालत पहुंच गए। इस दौरान त्विषा शर्मा के परिवार के सदस्य और उनकी कानूनी टीम भी अदालत परिसर में मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया ने समर्थ सिंह को घेर लिया और उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई लेकिन वह सवालों से बचता रहा। समर्थ सिंह के जिला न्यायालय पहुंचने की खबर मिलते ही त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा और उनके वकील अनुराग श्रीवास्तव भी जिला न्यायालय पहुंचे एवं समर्थ सिंह के आत्मसमर्पण का विरोध किया। श्रीवास्तव ने पत्रकारों से कहा कि समर्थ सिंह जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पहले भोजशाला में 'महा आरती' हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

धार/भाषा। मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर घोषित किए जाने के एक सप्ताह बाद शुक्रवार को सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने वहां 'महा आरती' में भाग लिया, जबकि मुसलमानों ने इस फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने घरों में नमाज अदा की।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को अपने फैसले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को मां वाग्देवी का मंदिर करार दिया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की अनुमति थी। इस फैसले से पहले हिंदू समुदाय को केवल मंगलवार को इस मध्यकालीन स्मारक में पूजा की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से यहां शुक्रवार की नमाज अदा करता आ रहा था। दोनों समुदाय इस स्थल पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहला जुम्मा था। हिंदू संगठनों ने इसे दो दशक से अधिक समय बाद परिसर में शुक्रवार को बड़े स्तर पर हुआ पहला धार्मिक आयोजन बताया। भोज उत्सव समिति और भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति ने परिसर में भजन-कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम और 'महा आरती' का आयोजन किया।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दिनभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा।

भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि धार और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। परिसर के गर्भगृह और अन्य हिस्सों को रंगोली एवं फूलों से सजाया गया था तथा श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए कतारों में नजर आए। हालांकि मुसलमानों ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने घरों और निजी परिसरों में जुमे की नमाज अदा की। स्थानीय मुस्लिम नेता अब्दुल समद ने कहा कि समुदाय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमने शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया। हमने अपने घरों में जुमे की नमाज अदा की और काली पट्टी बांधी।'' समद ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने परिसर के कमाल मौला मस्जिद हिस्से में शुक्रवार की नमाज की अनुमति रद्द किए जाने पर भी आपत्ति जताई।

इससे पहले समद ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में प्रशासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि भोजशाला परिसर के आसपास की कुछ गतिविधियां उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं थीं। उन्होंने प्रशासन द्वारा कुछ कार्यक्रमों और अनुमतियों को रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली। समद ने कहा, ''संविधान सभी समुदायों को समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है और हम उसके दायरे में रहकर आगे भी कार्य करेंगे।'' संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धार में करीब 2,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया। ड्रोन

आधुनिक यातायात और पर्यावरण अनुकूल विकास से 'मेट्रोपोलिस' बनेगी दिल्ली : संधू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को अब एक 'मेट्रो शहर' से 'मेट्रोपोलिस' बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मिलकर काम करने वाली सरकार, आधुनिक यातायात, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला विकास और आपदाओं से निपटने के मजबूत इंतजाम जरूरी हैं।

भारत-जापान संबंधों पर केंद्रित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका उप-शहर को वैश्विक निवेश और आर्थिक उन्नति के एक नए केंद्र के रूप में बदलने पर जोर दिया। दिल्ली के 'मेट्रोपोलिस' बनने का

रास्ता बताते हुए संधू ने कहा कि शहर अब उस दौर में पहुंच गया है जहां हमारा ध्यान सिर्फ इमारतें (बुनियादी ढांचा) खड़ी करने पर नहीं होना चाहिए। अब हमें पूरे शहर के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जो मुख्य रूप से आधुनिक यातायात, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले विकास, पानी व पर्यावरण प्रबंधन और आपदाओं से निपटने की मजबूती पर टिकी हो।

उपराज्यपाल ने समझाया कि एक 'मेट्रोपोलिस' सिर्फ बुनियादी ढांचे से नहीं, बल्कि अपनी दक्षता, टिकाऊपन, नई सोच और बेहतर जीवन स्तर से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय पूरे शहर को एक साथ जोड़कर विकसित करने पर होना चाहिए। दुनिया के अन्य बड़े शहरों से सीख लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्मार्ट यातायात पर काम करना चाहिए, जहां मेट्रो, बस और घर तक पहुंचाने वाले साधन एक डिजिटल मंच के जरिए बिना किसी रुकावट के जुड़े हों। उन्होंने कहा कि आधुनिक सूचना तंत्र और कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।

भारत ने डब्ल्यूटीओ में सौर पैनल मामले में चीन के अनुरोध पर रोक लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने सौर सेल, मॉड्यूल और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों के लिए अपने समर्थन उपायों को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दायर मामले में पैनल गठित करने के चीन के अनुरोध पर रोक लगा दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चीन ने इस महीने की शुरुआत में डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) से एक पैनल गठित करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध दोनों देशों के बीच परामर्श के विफल रहने के बाद किया गया था। चीन ने पिछले वर्ष दिसंबर में यह मामला दायर किया था।

जिनेवा स्थित एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने मामले में पैनल बनाने से संबंधित चीन के पहले अनुरोध को खारिज कर दिया है। डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत, मामले से संबंधित देश पहली बार पैनल गठन के अनुरोध को रोक सकता है, लेकिन दूसरी बार भी यह अनुरोध किए जाने पर पैनल गठित हो जाता है। यह मुद्दा 22 मई को जिनेवा में आयोजित डीएसबी की बैठक में उठा था। यदि चीन अगली बैठक में दोबारा अनुरोध करता है, तो पैनल का गठन स्वतः हो जाएगा।

बाह्य क्षेत्र के लिए चुनौती पेश कर रहे वित्तीय हालात, कच्चे तेल के दाम : आरबीआई बुलेटिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच वित्तीय हालात, कच्चे तेल की कीमतें और पूंजी प्रवाह बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य के लिए चुनौती बने हुए हैं। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक बुलेटिन में यह आकलन पेश किया गया। आरबीआई बुलेटिन में 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पश्चिम एशिया से जुड़ी अनिश्चितताओं की छाया बनी हुई है।

लेख कहता है कि अप्रैल में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूती बनी रही, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के कई खंडों में मजबूती देखी गई। कृषि क्षेत्र में मानसून-पूर्व बारिश के सामान्य से अधिक रहने और जलाशयों के संतोषजनक स्तर को देखते हुए ग्रीष्मकालीन बुवाई अच्छी रही। इसके मुताबिक, अप्रैल में खाद्य कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई जबकि मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर रही। पश्चिम एशिया का संघर्ष जिंस बाजारों, वैश्विक व्यापार प्रवाह और आपूर्ति शृंखलाओं पर लगातार दबाव डाल

रहा है, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। लेख में कहा गया, ''भारत मजबूत वृहद आर्थिक आधार के साथ इस दौर में कदम रख रहा है। घरेलू मांग से वृद्धि को प्रमुख रूप से समर्थन मिल रहा है, लेकिन निकट अवधि का परिदृश्य आपूर्ति पक्ष के दबावों के कारण कुछ हद तक प्रभावित है। सकल मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर के दायरे के भीतर बनी हुई है, लेकिन घरेलू कीमतों पर इसके प्रभाव की निगरानी जरूरी है। इसमें कहा गया, वित्तीय परिस्थितियां, कच्चे तेल की कीमतें और पूंजी प्रवाह बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि मजबूत सेवा निर्यात, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सकारात्मक प्रवाह, विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर और सरकार एवं आरबीआई के सक्रिय नीतिगत कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में मददगार होंगे।

देश में आयात शुल्क बढ़ने से 2026 में सोने की मांग में आ सकती है 50-60 टन की कमी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद देश में वर्ष 2026 के दौरान सोने की मांग 50-60 टन घट सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम होगी। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने यह बात कही है।

डब्ल्यूजीसी ने भारत के स्वर्ण बाजार पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, पूरे वर्ष 2026 को देखें तो आभूषण, सोने की छड़ और सिक्कों की संयुक्त मांग में लगभग 50-60 टन की कमी आ सकती है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत कम होगी। इसका मुख्य कारण आयात शुल्क में बढ़ोतरी है। सोने पर आयात शुल्क को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है और इससे जुलाई 2024 में की गई शुल्क कटौती पूरी तरह समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोगों से एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सोने की कीमत, आय स्तर में बदलाव, मुद्रास्फीति और मानसून जैसे अन्य कारक भी सालाना मांग को प्रभावित करेंगे। डब्ल्यूजीसी ने कहा, हमारे आर्थिक मॉडल बताते हैं कि आयात शुल्क में बदलाव का असर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में सोने की मांग पर पड़ता है। हालांकि, इसका प्रभाव आभूषण और निवेश उत्पादों जैसे सोने की छड़ तथा सिक्कों पर अलग-अलग होता है। निवेश मांग शुल्क बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जबकि आभूषण मांग अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहती है। डब्ल्यूजीसी के अनुसार, आभूषणों की मांग पर कीमतों और मुद्रास्फीति का अधिक असर पड़ता है, जबकि आयात शुल्क का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। इसका कारण यह है कि विवाह और सामाजिक आयोजनों के लिए आभूषणों की खरीद अक्सर आवश्यक मानी जाती है। वहीं, निवेश मांग आय स्तर और आयात शुल्क से जुड़ी होती है। अधिक शुल्क और पाबंदियां आमतौर पर मांग को प्रभावित करती हैं।

सीबीआई ने नीट-यूजी का भौतिकी का प्रश्नपत्र 'लीक' करने पर पुणे की प्रवक्ता को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2026 के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के भौतिकी के प्रश्नपत्र को लीक करके चुनिंदा अभ्यर्थियों को देने के आरोप में पुणे निवासी एक महिला प्रवक्ता को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने पुणे के सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में कार्यरत मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया और उन्हें प्रश्नपत्र लीक होने का एक अन्य 'स्रोत' बताया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''सीबीआई ने नीट-यूजी के भौतिकी के प्रश्नपत्र लीक करने वाली एक अन्य प्रमुख आरोपी की पहचान कर ली है।''

एजेंसी ने आरोप लगाया कि हवलदार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के बाद नीट-यूजी प्रक्रिया में शामिल थीं। बयान में कहा गया है, ''भौतिकी के प्रश्नपत्र तक उनकी पूरी पहुंच थी। अप्रैल में उन्होंने कुछ प्रश्न सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ साझा किए थे।'' सीबीआई ने 16 मई को पुणे में रहने वाली वनस्पति विज्ञान की शिक्षका मंधारे को नीट-यूजी के प्रश्नपत्र लीक करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पाया कि हवलदार द्वारा उम्मीदवारों के साथ साझा किए गए प्रश्न नीट(यूजी)-2026 के भौतिकी के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।

सीबीआई ने कहा, ''सीबीआई ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए। जब्त की गई वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण जारी है।'' राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 12 मई को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तीन मई को आयोजित नीट-यूजी को रद्द कर दिया था और पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है।

जैव विविधता अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों से व्यापार में आसानी हुई : भूपेंद्र यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में किए गए हालिया संशोधनों से उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है और व्यापार करने में आसानी होगी। मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदायों को उद्योगों से उचित लाभ मिल रहा है।

यादव ने कहा, ''देशभर में लाभार्थियों को लगभग 145 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 11,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लाभ हुआ है।'' उन्होंने ये टिप्पणियां भोपाल में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस -2026 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के

दौरान कीं। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्थक वैश्विक परिणाम केवल सशक्त स्थानीय कार्रवाई, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ जीवनशैली के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ''सामुदायिक नेतृत्व वाली संरक्षण परंपराएं जैसे उपवन, पारंपरिक किस्में, देशी नस्लें और स्थानीय प्रबंधन प्रथाएं लोगों और प्रकृति के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी संबंध को दर्शाती हैं।''

गुजरात : अकासा एयर कार्गो से 2.58 करोड़ रुपए का सोना चोरी होने के मामले में आठ गिरफ्तार

अहमदाबाद/भाषा। शहर में अकासा एयर कार्गो से 2.58 करोड़ रुपए मूल्य के 2.1 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण चोरी होने के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त जोन-4 अतुल कुमार बंसल ने बताया कि 18 मई को लॉजिस्टिक्स कंपनी ने अकासा एयर की कार्गो सेवा के जरिये सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोने के आभूषणों से भरे सात पार्सल भेजे थे जिनमें से एक पार्सल गायब था।

उन्होंने बताया कि पार्सल में 2.1 किलोग्राम सोने के आभूषण थे। अतुल कुमार बंसल ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज आदि का उपयोग कर मामले की जांच की और अकासा एयर के कर्मचारियों से जुड़े पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया।

'कॉकरोच जनता पार्टी' ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान शुरू किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत में अपने मूल 'एक्स' खाते को प्रतिबंधित किए जाने के बाद कॉकरोच मरता नहीं है टैगलाइन के साथ वापसी करते हुए, व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया।

सीजेपी के नए 'एक्स' हैंडल - कॉकरोच इज बैक - और इसके इंस्टाग्राम मंच के माध्यम से शुरू किया गया यह अभियान शिक्षा क्षेत्र में कथित प्रणालीगत विफलताओं पर केंद्रित है, विशेष रूप से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक 2026 पेपर-लीक विवाद से संबंधित चिंताओं पर।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वालों से प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाली ऑनलाइन याचिका का समर्थन करने का आग्रह किया।

दीपके ने एक वीडियो संदेश में कहा, कैसे हो तुम सब कॉकरोच? सब कह रहे हैं कि तुम इंटरनेट पर खूब मजे कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का समय आ गया है। आज हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए एक याचिका शुरू कर रहे हैं।

जवाबदेही की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली की विफलताओं ने छात्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाए। व्यवस्था की गलती के कारण ही 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, व्यवस्था की गलती के कारण ही नीट के छात्रों ने आत्महत्या की। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए

तीन मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) को पेपर लीक के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा हाल ही में रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है और 21 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी।

दीपके ने प्रधान के खिलाफ अभियान के दौरान धमकियां मिलने का भी दावा किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

इस्तीफे के लिए अभियान उस घटना के एक दिन बाद शुरू हुआ जब 'एक्स' द्वारा भारत में मूल सीजेपी हैंडल पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद दीपके ने एक नया हैंडल - कॉकरोच इज बैक - शुरू किया, जिसकी टैगलाइन है - कॉकरोच कभी मरता नहीं।

दीपके ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सरकार का दांव उलटा पड़ गया है।

उनके अनुसार, 'एक्स' द्वारा सीजेपी खाते को बंद किए जाने से पहले इसके मूल खाते पर दो लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। शुक्रवार दोपहर तक, लॉन्च होने के लगभग 24 घंटे बाद, कॉकरोच इज बैक के हैंडल पर 1.65 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके थे।

इंस्टाग्राम पर, सीजेपी के शुक्रवार दोपहर तक 2.05 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर गया, जिससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसके मेटा के स्वामित्व वाले मंच पर लगभग 91 लाख फॉलोअर्स हैं, और साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसके लगभग 1.34 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उससे काफी पीछे रह गईं।

'एक्स' पर 2.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ अब भी भाजपा का वर्चस्व है जबकि कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल के 1.15 करोड़ फॉलोअर हैं।

कर्नाटक मंत्रिमंडल फेरबदल

30 से अधिक विधायक दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मिलेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिवमोगा। कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के कम से कम 30-35 विधायक 28 या 29 मई तक राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करेंगे ताकि पार्टी नेतृत्व पर मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का दबाव बनाया जा सके और उनमें से लगभग 20 को मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर मिले। उन्होंने मांग की है कि सरकार के सत्ता में तीन साल पूरे होने के 15 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि फेरबदल नहीं हुआ और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल नहीं किया गया तो वे कड़ा निर्णय ले सकते हैं।

कृष्णा ने कहा, पहले यह तय किया गया था कि केरल के मुख्यमंत्री का चुनाव होने के बाद दिल्ली का दौरा किया जाए। अब जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है, तो हम दो-तीन दिनों में मुलाकात करेंगे और हममें से 30-35 विधायक दिल्ली जाएंगे। इस बार हमारे सामने करो या मरो की स्थिति है क्योंकि सरकार बने तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई चर्चा नहीं हो रही है।उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाल ही में कहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और 15 नए लोगों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस विधायक ने कहा, हमने 20 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि जो लोग अभी मंत्री हैं, वे तीन साल से सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमने 28 या 29 मई तक दिल्ली जाने का फैसला किया है। पहले हममें से 25 लोग गए थे। अब संख्या बढ़ गई है, इसलिए लगभग 35 लोग जा सकते हैं।

यह रेखांकित करते हुए कि मुख्यमंत्री परिवर्तन का मुद्दा शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर है, कृष्णा ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर आपको नेतृत्व से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल में फेरबदल कर हमें मंत्री पद दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हम इसे ऐसे ही जारी नहीं रहने देंगे। हमें 15 दिनों के भीतर अवसर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास अन्य योजनाएं हैं और हम उन पर निर्णय लेंगे।

खबरों के अनुसार, मंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले कुछ कांग्रेस विधायक पहले से ही दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात के लिए मौजूद हैं।

स्वागत

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलूरु में अपने घर पर एक मीटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का स्वागत करते हुए।

लाडले मशक मामले के दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापसी पर कांग्रेस और भाजपा में वाकयुद्ध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को लाडले मशक दरगाह दंगा मामले में कथित तौर पर शामिल मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। कांग्रेस ने कहा है कि यह मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया था, जबकि भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कलबुर्गी जिले के आलंद स्थित लाडले मशक दरगाह में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामलों को वापस लेने का फैसला किया। इसकी भाजपा नेताओं ने कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कदम कानून और व्यवस्था की कीमत पर अल्पसंख्यक समूहों का तुष्टीकरण करने के समान है।

यह मामला एक मार्च, 2022 का है, जब कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरगाह के अंदर शिवलिंग के शुद्धिकरण का अनुष्ठान करने की मांग की थी। इस मुद्दे के कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप इलाके में निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये मामले उनके (मुसलमानों के) खिलाफ राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए थे। हमने किसानों के खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं। हमने कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं। हमने विरोध प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामलों को वापस लेना विभिन्न समूहों से जुड़े आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों के संबंध में पहले लिए गए निर्णयों के अनुरूप था। शिवकुमार ने इस आरोप का खंडन किया कि यह कदम किसी विशेष समुदाय को खुश करने के उद्देश्य से उठाया गया था। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विभिन्न संगठनों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के कैबिनेट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह कदम कैबिनेट की एक उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। विजयेंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राज्य में अब कांग्रेस सरकार द्वारा वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का निर्लज्ज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। न्यूनतम जिम्मेदारी का भी पालन न करते हुए, नैतिकता, गरिमा और शालीनता को ताक पर रखकर यह तुगलक शैली की कांग्रेस सरकार सभ्यता की हर सीमा को पार कर चुकी है।

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री वी सुनील कुमार ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लाडले मशक मामले में मुकदमों को वापस लेने की तुलना किसानों या कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने से नहीं की जा सकती।

बीदर चिकित्सा संस्थान में भीड़ ने चिकित्सक पर हमला किया

बीदर।कर्नाटक में यहां बीदर चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कुछ लोगों के एक समूह ने बृहस्पतिवार की देर रात एक चिकित्सक पर कथित तौर पर हमला कर दिया जिसके बाद चिकित्साकर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार, तुकाराम भालके मरीजों का इलाज कर रहे थे तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और गंभीर रूप से घायल एक मरीज विजय सिंह का इलाज करने के लिए कहने लगे। पुलिस ने बताया कि ये लोग चाहते थे कि चिकित्सक उसका नाम दर्ज किए बिना ही उसका इलाज करे।

चिकित्सक ने उन्हें इलाज करने के लिए ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) रजिस्टर में मरीज का नाम दर्ज करने पर जोर दिया, तो लगभग 12 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि अन्य कर्मचारी भालके की मदद के लिए आए और लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे उन पर हमला करते रहे। इस घटना के बाद, आक्रोशित डॉक्टरों ने घटना की निंदा करते हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और वे हड़ताल पर चले गये।

राहुल गांधी के विवादित बयान पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने की माफी की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भाजपा सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पूरे देश का अपमान किया है।

बसवराज बोम्मई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री मोदी को संविधान के अनुसार तीन बार पीएम के रूप में चुना गया है और विश्व के नेताओं ने उनके नेतृत्व की प्रशंसा की है। भारत के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और कई वैश्विक नेताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए बोम्मई ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और उन्होंने दावा किया कि इस कदम से आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने में मदद मिली। उन्होंने आगे कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए सरकार ने पाकिस्तान को कथित तौर पर आतंकवादियों का समर्थन और उन्हें प्रायोजित करने के लिए सबक सिखाया है और यह भी कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में वे एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ 'निम्न स्तर की टिप्पणी' नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को संवैधानिक पद का अपमान करार दिया।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला करते हुए दावा किया कि हाल के चुनावों में पांच में से चार राज्यों में पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है।

मुश्किल ब्रेन और स्पाइन सर्जरी अब हुई और आसान व एडवांस्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। एडवांस्ड न्यूरोसाइंस केयर के लिए एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल ने न्यूरोसर्जरी के लिए दो स्टेट ऑफ़ दि आर्ट रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म स्पाइन सर्जरी के लिए मॉजर दि रोबोटिक गाइडेंस सिस्टम तथ क्रेनियल और ब्रेन प्रक्रिया के लिए एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम(आरओएसए) लॉच किया है, जिससे सर्जन बहुत मुश्किल प्रक्रिया को ज़्यादा सटीकता, बेहतर सुरक्षा और मरीज़ की तेज़ी से रिकवरी के साथ कर सकते हैं। रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने एस्टर सीएमआई अस्पताल के वरिष्ठ डाक्टरों की उपस्थिति में किया। आरओएसए रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पेश की गई एक बड़ी कामयाब फ्रेमलेस ब्रेन सर्जरी टेक्नोलॉजी है, जो भारत में न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया करने के तरीके को बदल रही है। पहले दिमाग के शल्य प्रक्रिया में सर्जिकल नेविगेशन के लिए मरीज़ की खोपड़ी पर कड़े फ्रेम लगाने की ज़रूरत होती थी पर आरओएसए की फ्रेमलेस रोबोटिक टेक्नोलॉजी से सर्जन अब पारंपरिक फ्रेम-बेस्ड सिस्टम से जुड़ी परेशानी और इनवेसिवनेस(छेद) के बिना सब-मिलीमेट्रिक प्रिसिजन हासिल कर सकते हैं।

मॉजर दि रोबोटिक गाइडेंस सिस्टम स्पाइन सर्जरी के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सर्जनों को स्पाइनल इम्प्लांट की बहुत सटीक प्लानिंग और प्लेसमेंट में मदद करेगा। यह टेक्नोलॉजी सर्जिकल एक्युरेसी को बढ़ाती है, इंसानी गलती व रेडिएशन एक्सपोजर को कम करती है और मिनिमली इनवेसिव तरीकों के मदद से छोटे चीरे लगाकर व खून का नुकसान व हॉस्पिटल में लगने वाले समय को कम करने की जाती है। इस मौके पर अस्पताल के न्यूरोसाइंसेज और लीड कंसल्टेंट डॉ. रवि गोपाल वर्मा, न्यूरोसर्जरी और स्पाइन सर्जरी सलाहकार डॉ. अक्षय हरि, डॉ. प्रशांत एन आदि उपस्थित थे।

मंत्रिमंडल ने 52 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया: परमेश्वर

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के मंत्रिमंडल के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम मंत्रिमंडल की एक उपसमिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसने प्रत्येक मामले की विस्तार से समीक्षा की थी। मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य भर के विभिन्न थानों में दर्ज 52 आपराधिक मामलों को अभियोजन से वापस लेने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने कहा, कन्नड़ समर्थक संगठन और किसान संगठन कई वर्षों से अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर ज्ञापन दे रहे थे। सरकार ने प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार-विमर्श करने के बाद इसे मंत्रिमंडल की एक उपसमिति को भेज दिया। उपसमिति ने पाया कि इन मामलों को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है। उन्होंने बेंगलूरु में पत्रकारों से कहा कि राज्य भर के विभिन्न संगठनों के खिलाफ 52 मामले कल मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए थे और उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया।

भाजपा विधायक ने कक्षाओं में हाजिरी के समय 'यस सर' के बजाय 'जय श्री राम' बोलने का समर्थन किया

बेंगलूरु। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने पार्टी के पूर्व नेता एवं विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के उस कथित बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों से कक्षा में हाजिरी के दौरान शिक्षकों द्वारा नाम पुकारे जाने पर 'यस सर' के बजाय 'जय श्री राम' कहकर जवाब देने का आह्वान किया है। पूर्व मंत्री रेड्डी का हालिया बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। रेड्डी ने कहा, हालांकि यतनाल का अब हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है: कि स्कूल में हाजिरी के दौरान, जब शिक्षक छात्रों का नाम पुकारें, तो उन्हें 'यस सर' के बजाय 'जय श्री राम' कहना चाहिए। मैं इस आह्वान का शत प्रतिशत समर्थन करता हूं। उन्होंने हाल में कोप्पल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जब भी मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाता हूं, तो मैं भी इसी तरह की अपील करता हूं... विद्यार्थी भगवा शॉल और भगवा पगड़ी पहनकर आएं; हम भारतीय हैं, यह हिंदुत्व का मामला है, हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का। ये टिप्पणियां सरकार के उस फैसले पर प्रतिक्रिया प्रतीत होती हैं जिसमें विद्यार्थियों को स्कूलों में हिजाब और अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 2022 के आदेश को पिछले सप्ताह वापस ले लिया था।

रोजगार मेले में आज 51 हजार उम्मीदवारों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । रोज़गार मेले के हिस्से के तौर पर शनिवार को पूरे भारत में अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए 51 हजार से ज़्यादा उम्मीदवारों को वर्चुअली रोजगार पत्र बांटे जाएंगे। इस रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर बेंगलूरु में शनिवार को सुबह 9.30 बजे से अनुग्रह सामुदायिक हॉल में आयोजित इस रोजगार मेले के केन्द्रीय लघु, मध्यम और छोटे उद्योग, श्रम व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
टॉवर-एफ, एनबीसीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

रिक्ति परिपत्र संख्या: 01/2026-27
सूचना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद/कोलकाता/ भोपाल/ बेंगलुरु में परामर्शदाता - निजी सचिव (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (मुख्यालय) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, **हैदराबाद/कोलकाता/भोपाल/बेंगलुरु** में अनुबंध के आधार पर एक परामर्शदाता सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (निजी सचिव) की नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

नियुक्ति हेतु विस्तृत नियम और शर्तें, योग्यता तथा अनुभव ट्राई की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन **ऑनलाइन मोड के माध्यम से URL: https://vacancies.trai.gov.in** पर भेज सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **04 जून 2026** है।

CBC 06202/12/0014/2627

एएमएमके प्रमुख ने मेकेदाटु परियोजना पर कर्नाटक के रुख की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) प्रमुख टी.टी.वी. दिनाकरन ने शुक्रवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस टिप्पणी को अहंकार भरी बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को कावेरी नदी पर बने मेकेदाटु बांध का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मेकेदाटु जलाशय के निर्माण पर कर्नाटक का लगातार जोर देने से कावेरी डेल्टा का बड़ा हिस्सा सूख जाएगा और किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए, दिनाकरन ने कहा कि कर्नाटक सरकार जल्द ही बांध के लिए एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए प्रभावित राज्यों की सहमति आवश्यक है, और कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु को समय पर पानी का उसका उचित हिस्सा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, कर्नाटक सरकार एकतरफा कार्रवाई करने पर अड़ी हुई है। दिनाकरन ने आरोप लगाया कि इस जल्दबाजी से तमिलनाडु के किसानों के जीवन और आजीविका को खतरा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राजनीतिक सत्ता हासिल करने की होड़ में तमिलनाडु के अधिकारों को कर्नाटक सरकार के पास गिरवी रख दिया था।

उन्होंने कहा कि किसानों और आम जनता के बीच अब यह संदेह और भय पैदा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सत्ता में आई तमिलनाडु की मौजूदा सरकार राजनीतिक सत्ता बरकरार रखने के लिए कावेरी मुद्दे पर राज्य के अधिकारों को भी त्याग सकती है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से राज्य के अधिकारों और किसानों के कल्याण को मान्यता देने का आग्रह करते हुए, कावेरी नदी पर मेकेदाटु बांध के निर्माण के कर्नाटक सरकार के प्रयास को जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया।

कर्नाटक ने कावेरी नदी पर मेकेदाटु में एक संतुलन जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है ताकि वह अपनी पेयजल और बिजली उत्पादन की जरूरतों को पूरा कर सके। तमिलनाडु ने इस परियोजना का विरोध करते हुए कहा है कि इसके लागू होने पर उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संबोधन

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद (बीच में), शुक्रवार को बेंगलूरु, कर्नाटक में महाराजा कप 2026, जो राज्य में केएससीए की प्रीमियर टी 20 लीग है, की घोषणा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
(निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग)
इसरो टेलिमेट्रि ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक)
प्लाट नं. 12 एवं 13, तीसरा मेन, द्वितीय फेज,
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु-560058
फोन : 080-28094541, 4185, 4144

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के ठेकेदरों से एनआईटी में निम्नलिखित कार्यों के लिए नग दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

1	कार्य का नाम	आईडीएसएन परिसर, इसट्रैक, ब्याललू, बेंगलूरु में डीसी ब्रेकर्स, युनिन्यविन (Uninyvin) केबल्स और बैटरी बैंक स्टैंड्स की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य।
2	एनआईटी सं	इस्ट्रैक/सीएमजी/ई/एमएआईएनटी/ईटीएन-10 /2026-2027 दिनांक 22.05.2026
3	निविदा का अनुमानित मूल्य	रु. 20.48 लाख
4	निविदा दस्तावेज विवरण	ई-निविदा
5	कार्यादेश जारी होने के 15 दिन बाद की तिथि से गिनी जाने वाली कार्य समापन अवधि	तीन (03) महीने
6	निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	23.05.2026 को 16.00 बजे से 06.06.2026 को 16.00 बजे तक
7	बोली स्पष्टीकरण	24.05.2026 को 11.00 बजे से 07.06.2026 को 16.00 बजे तक
8	बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख	08.06.2026 को 16.00 बजे तक
9	निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	09.06.2026 को 16.00 बजे तक
10	निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	11.06.2026 को 11.00 बजे से
11	अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	रु. 40,960/-

पात्रता मानदंड और दूसरी जानकारी के लिए, इच्छुक निविदाकार कृपया वेबसाइट www.isro.gov.in/Tenders.html पर टेंडर इनवाइटिंग का विस्तृत द्विभाषी (हिंदी - अंग्रेजी) नोटिस (NIT) देख सकते हैं और https://www.tenderwizard.com/ISRO पर टेंडर फ्री में देख सकते हैं।
ह/- समूह प्रमुख- सीएमजी

रामा-श्यामा की परंपरा गांवों की सबसे बड़ी खूबसूरती : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह-सुबह गांव में भ्रमण कर आमजन से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में पैदल चलते हुए कहीं बुजुर्गों की कुशलक्षेम पूछते हुए उनका आशीर्वाद लिया तो कहीं स्थानीय दुकानदारों से उनके व्यवसाय एवं दैनिक गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री की सादगी एवं आत्मीयता देखकर ग्रामीण अभिभूत नजर आए। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान जगह-जगह रुककर लोगों की समस्या एवं सुझाव सुनते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीण परिवेश की आत्मीयता का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, सुख-दुख साझा करते हैं जिससे आपसी मेलजोल बना रहता है। रामा-श्यामा की यही परंपरा गांवों की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चाय पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिससे गांव के युवाओं को इन केन्द्रों पर पुस्तकें, समाचार पत्र और अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो रही है। इससे युवाओं पर आर्थिक भार कम होगा और वे गांव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के पानी के उचित प्रबंधन और तालाबों के संरक्षण से गांवों में जल संकट की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनसहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी से ही जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। इसी दिशा में राज्य सरकार गंगा दशहरा (25 मई) से 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' प्रारंभ करने जा रही है।

इस अभियान के माध्यम से जनभागीदारी के साथ गांवों में जल संरक्षण एवं जल संचयन के कार्य किए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोवर्धन नाथ जी मंदिर एवं माताजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में बैडमिंटन खेल रहे बच्चों के बीच पहुंचकर स्वयं भी उनके साथ बैडमिंटन खेला और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री के साथ बैडमिंटन खेलकर बच्चे बहुत खुश हुए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्नेहपूर्वक बात करते हुए उन्हें चॉकलेट भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जिले में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को गांव के खेमसागर तालाब पर पाल निर्माण एवं पौधारोपण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर खेल सुविधाओं के विस्तार एवं राजकीय विद्यालय में कक्षा कक्षों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकताः मुख्यमंत्री शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' शुरू करेगी। शर्मा शुक्रवार सुबह डूंगरपुर जिले के धम्बोला गांव में घूमे और आम लोगों से सवांद किया। मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में पैदल चलते हुए बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानी, उनका आशीर्वाद लिया तो कहीं स्थानीय दुकानदारों से उनके व्यवसाय एवं दैनिक गतिविधियों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि शर्मा ने रात्रि विश्राम इसी गांव में किया था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के पानी के उचित प्रबंधन और तालाबों के संरक्षण से गांवों में जल संकट की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। राज्य सरकार गंगा दशहरा (25 मई) से 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' शुरू करने जा रही है। इस अभियान के माध्यम से जनभागीदारी के साथ गांवों में जल संरक्षण एवं जल संचयन के कार्य किए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जिले में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को गांव के खेमसागर तालाब पर पाल निर्माण एवं पौधारोपण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर खेल सुविधाओं के विस्तार एवं राजकीय विद्यालय में कक्षा कक्षों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने गांव में बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला और उनका उत्साहवर्धन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोवर्धन नाथ जी मंदिर एवं माताजी मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की।

'नाट्यशास्त्र : पंचम वेद पर एकाग्र' का लोकार्पण राज्यपाल बागड़े ने किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। नाट्यशास्त्र पर आधारित ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र : पंचम वेद पर एकाग्र' का विमोचन शुक्रवार को यहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया और भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में की गई इस पहल को सराहा। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला द्वारा प्रकाशित 'नाट्यशास्त्र : पंचम वेद पर एकाग्र' का संपादन कला मर्मज्ञ डॉ. राजेश कुमार व्यास ने किया है। इस ग्रंथ में देश के मर्मज्ञ विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में नाट्यशास्त्र के विविध आयामों पर लिखा है। आधिकारिक बयान के अनुसार लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में बागड़े ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर की गई इस पहल की सराहना करते हुए संपादक लेखक डॉ. राजेश कुमार व्यास को बधाई देते हुए उनकी सराहना की।

उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में यह महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इससे पाठकों को नाट्यशास्त्र ग्रंथ को समझने की नई और मौलिक दृष्टि मिल सकेगी। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक फुरकान खान द्वारा ग्रंथ प्रकाशन के लिए की गई पहल की भी सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)राजकुमार सागर भी उपस्थित रहे।

साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डॉ. व्यास के अनुसार इस पुस्तक में कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत के अतिथि आचार्य और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कुलपति रहे डा. राधावल्लभ त्रिपाठी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध नाटककार डॉ. अर्जुन देव चारण, नाट्यशास्त्र के विद्वान पीयाल भट्टाचार्य, सिनेमा-मर्मज्ञ ज्ञानेश उपाध्याय, कला मर्मज्ञ नर्मदा प्रसाद उपाध्याय व संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव सुमन कुमार सहित अन्य हस्तियों ने अपनी मौलिक दृष्टि से नाट्यशास्त्र की व्याख्या की है। पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह के दो दुर्लभ लेख भी हैं। ग्रंथ के संपादक डॉ. व्यास देश के जाने-माने संस्कृतिकर्मी, कलाविद और नाट्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनकी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अब तक 27 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

गाय को मारने पर पाबंदी लगे और उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए : सैयद सरवर चिश्ती

जयपुर। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से अपील की कि गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित किया जाए तथा पूरे देश में उसे मारने एवं बलि देने के लिए उसकी होने वाली बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। मौलवी की यह अपील 28 मई के ईद-उल-अजहा से कुछ दिन पहले आई है। चिश्ती ने कहा कि हिंदू समुदाय के लिए गाय का बड़ा धार्मिक महत्व है तथा वह सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा की हकदार है।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वह संसद का विशेष सत्र बुलाएं ताकि गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने वाला कानून लाया जा सके। चिश्ती ने कहा, यह देखना जरूरी है कि इस तरह के विधेयक का कौन समर्थन और कौन विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक सम्मान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। चिश्ती ने कहा कि मुसलमान ऐसे कदम का स्वागत करेंगे। उन्होंने मवेशियों को लावारिस छोड़ने के खिलाफ भी सख्त कानून बनाने की मांग की ।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए का रवैया गैर-जिम्मेदाराना : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए एजेंसी के रुख को गैर-जिम्मेदाराना बताया। गहलोत ने दावा किया कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने एक संसदीय समिति से कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि नीट का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। उन्होंने कहा, एक तरफ एनटीए ने स्वयं परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं दूसरी ओर उसके अध्यक्ष इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि जयपुर में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन होने के बावजूद भाजपा सरकार और प्रशासन अब भी गहरी नींद में है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदर्शन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों लोग एकत्र हुए थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कथित पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के नाम सामने आने के कारण अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आमतौर पर भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर चला देती हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि इसमें भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं।

रिश्वत मामले में दो शिक्षक गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शुक्रवार को टोंक में एक विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों को छात्र से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार इस प्रकरण में डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय (निवाई) में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मीनू गंगल व सहायक प्रोफेसर रमेश चन्द मीणा को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के बयान के अनुसार परिवादी ने शिकायत दी थी कि वह इस निजी विश्वविद्यालय में बीएड का दो वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि आरोपी डॉ. मीनू गंगल व रमेश चन्द मीणा ने उसकी अनुपस्थिति को सही करने व मुख्य परीक्षा में बैठाने तथा प्रवेश पत्र देने के एवज में उससे 23,000 रूपये बतौर रिश्वत मांगे। ब्यूरो की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। शुक्रवार को टीम ने जाल बिछाया और इस दौरान आरोपी गंगल ने अपने कार्यालय में परिवादी से रिश्वत राशि अपने सहयोगी व दूसरे आरोपी मीणा को दिलाई। टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे जांच की जा रही है।

राजस्थान में कई जगह धूल भरी आंधी व तेज हवाएं चलने का अनुमान

जयपुर। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से बेहाल राजस्थान के अनेक इलाकों में शुक्रवार से धूल भरी आंधी व तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी व उत्तरी भागों में 22-23 मई को दोपहर बाद बादल गरजने व कहीं-कहीं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।

इसी तरह आज व कल राज्य के कुछ भागों में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज धूल भरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। साथ ही 24 मई से तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने और राज्य के कुछ भागों में 'हीटवेव' व कहीं-कहीं तीव्र 'हीटवेव' का अनुमान है।

सहकारी मॉडल पर आधारित चुनिंदा कम्पनियों की खाद ही बिक्री करेंगी सहकारी समितियां : दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इफको एवं कृभको के अधिकारियों को पाबंद किया है कि राज्य में उर्वरक वितरण का कार्य पूर्ण रूप से क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए निजी डीलरों के माध्यम से उर्वरक वितरण पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। दक शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण सुनिश्चित होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सकेगी तथा कालाबाजारी की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि जिन ब्लॉकों में अभी सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया एवं डीएपी आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां आगामी दिनों में वितरण तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने नकली खाद पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के माध्यम से केवल इफको-कृभको आदि सहकारी मॉडल पर आधारित चुनिंदा कम्पनियों की खाद ही बिक्री की जाए। उन्होंने सभी जिला उप रजिस्ट्रार एवं निरीक्षकों को सहकारी समितियों के गोदामों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अन्य किसी कम्पनी के उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध न हों। उन्होंने निरीक्षण के फोटोग्राफ्स भी अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए।

दक ने कहा कि किसान हित में सहकारी आंदोलन की भावना के अनुरूप उर्वरक वितरण व्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी जिलों एवं प्रत्येक ब्लॉक में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए तथा इसके लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसान अभी नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति पूरी तरह तैयार नहीं हैं। ऐसे में नैनो उर्वरकों की अनिवार्य बिक्री के बजाय पहले किसानों को इसके लाभों की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश की सहकारी संस्था 'मार्कफेड' की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल मध्य प्रदेश भेजने के निर्देश भी प्रदान किए।

राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव 18 जून को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होगा। इस राज्य से तीन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है जिसके मद्देनजर यह द्विवार्षिक चुनाव करवाया जाएगा। राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य कांग्रेस के नीरज डांगी और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत तथा रवनीत सिंह का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। इसके अनुसार चुनाव के लिए अधिसूचना एक जून को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है। नामांकन पत्रों की जांच नौ जून को होगी और उम्मीदवार 11 जून तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। जरूरी होने पर मतदान 18 जून को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि वोटों की गिनती उसी दिन शाम पांच बजे शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। फिलहाल इनमें भाजपा और कांग्रेस के पांच-पांच सदस्य हैं। राज्य की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टियों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाजपा के उक्त तीन में से दो सीटें जीतने की उम्मीद है। राज्य विधानसभा में भाजपा के 118 विधायक हैं तथा कांग्रेस के 67 सदस्य हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के दो विधायक, भारत आदिवासी पार्टी के चार विधायक, राष्ट्रीय लोक दल का एक विधायक है।

न्यायालय ने पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि राज्य में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जुलाई तक करवाए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को भी निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट 20 जून तक जमा करे। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लंबित होने और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये चुनाव करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था। खंडपीठ ने इससे पहले 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला कई याचिकाओं पर उच्च न्यालालय के 14 नवंबर 2025 के आदेश से संबंधित है।

अदालत ने अपने उस आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पंचायत व नगरपालिकाओं के लंबित चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाए। हालांकि सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनावों को टालने की मांग की थी।

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही हो सुनिश्चित : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपये के 31 नवीन प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही बैठक में विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों,एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की गई। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में विभाग द्वारा अब तक स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य आगामी माह में पूर्ण कर लिए जाएंगें, जिनमें राजकीय महाविद्यालय, सीकरी, भरतपुर, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, मसूदा, अजमेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ाजान, कामां, भरतपुर के भवन निर्माण आदि कार्य है। भगत ने बताया कि शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध : अम्बरीष कुमार

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने जयपुर शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों का आकस्मिक निरीक्षण कर पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लिया। यह निरीक्षण पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ने कुल 6 पंप्स का निरीक्षण किया। टोंक रोड एवं मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर तीनों तेल कंपनियों, आइओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की उपलब्धता की जाँच की गई। साथ ही पेट्रोल पंप्स पर ईंधन सही मात्रा में नोजल से दिया जा रही है, इसकी भी विस्तृत जाँच विधिक माप विज्ञान अधिकारी के मार्फ़त की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ने विभिन्न पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्टाफ सदस्यों से बातचीत कर स्टॉक एवं आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से भी संवाद किया तथा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण में पाया गया कि किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कोई कमी नहीं है ।

मुलाकात — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बैठक की तस्वीर साझा की। पोस्ट में कहा गया, ''पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।''

हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

देवरिया (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि 'हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है।' योगी ने यहां 655 करोड़ रुपए की 19 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली सरकार है। हम समस्याएं नहीं, समाधान देते हैं, तभी जनता जनार्दन हमें चुनती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है तथा अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है।

एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश ने नए भारत का दर्शन किया है तथा प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से अवसंरचना विकास को प्राथमिकता दी, क्योंकि गति जितनी तेज होगी,

विकास का लाभ उतनी ही तेजी से आम जनता तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से कहा कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और नए सत्र से इसे शुरू करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय किसानों को आधुनिक तकनीक, कम लागत और अधिक उत्पादन की दिशा में नई राह दिखाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह गोरखपुर से सांसद थे, तब उन्हें अक्सर देवरिया आना पड़ता था। उन्होंने कहा, ''उस समय राज्य में अराजकता, उत्पीड़न और तुष्टीकरण की राजनीति थी। गोरखपुर से देवरिया तक सड़कें बदहाल थीं, कई हिस्सों में सिंगल लेन मार्ग था और चौरी-चौरा रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों जाम लगता था। लेकिन आज वही देवरिया फोर लेन कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है।''

योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और अन्य मजबूत बुनियादी ढांचे ही रोजगार एवं निवेश की नींव होते हैं।

बाराबंकी: किराना कारोबारी के घर फिल्मी अंदाज में डकैती,एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी-जेवर लूटे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बाराबंकी (उप्र)/भाषा। बाराबंकी जिले में देवा थानाक्षेत्र के ग्वारी गांव में शुक्रवार तड़के सात हथियारबंद डकैतों ने किराना कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया और उसके घर से करीब 1.02 करोड़ रुपए की नकदी एवं जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि वारदात के दौरान बच्चों तक को नहीं बख्शा गया।

पुलिस के अनुसार तड़के डकैत देवा-बाराबंकी मार्ग पर दरवाजा तोड़कर किराना कारोबारी आलोक जायसवाल के घर में पीछे से घुसे, उस वक्त परिवार के लोग गहरी नींद में थे। पुलिस के मुताबिक घर में आलोक, उनकी पत्नी, बेटा हिमांशु, बहू, मायके आईं दो बेटियां और एक मासूम बच्चा मौजूद थे। पुलिस के अनुसार डकैतों ने पूरे परिवार को एक जगह बैठा दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए सभी मुंह पर टेप चिपका दिया। उन्होंने रोने पर बच्चों को पीटा। पुलिस का कहना है कि करीब एक घंटे तक बदमाश अलमारियां, लॉकर और घर का कोना-कोना खंगालते रहे। पीड़ित परिवार के मुताबिक डकैत करीब 12 लाख रुपए नकद और लगभग 90 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर ले गए। सुबह करीब 4:22 बजे सभी डकैत फरार हो गए। बाद में परिवार ने खुद को मुक्त कर पुलिस को सूचना दी।

भाजपा की बंगाल जीत भारत की आर्थिक दिशा को बदल सकती है : प्रदीप गुप्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत न केवल राज्य के भविष्य को बल्कि पूरे देश की आर्थिक दिशा को भी बदल सकती है। उन्होंने इसके पीछे पूर्वी भारत के विशाल प्राकृतिक संसाधनों, बंदरगाहों और अब तक पूरी तरह इस्तेमाल न हो सकी व्यापारिक संभावनाओं को अहम कारण बताया।

'एक्सिस माई इंडिया' के संस्थापक-अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का सामूहिक रूप से अत्यधिक आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। उन्होंने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, ''यह सिर्फ बंगाल का

मामला नहीं है। वहां की जीत पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकती है।'' वह पश्चिम बंगाल में भाजपा की चुनावी जीत और 15 वर्षों बाद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाए जाने के व्यापक प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे। गुप्ता के अनुसार, पूर्वी भारत का महत्व उसके प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री पहुंच और पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संपर्क के कारण है। पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंडमान द्वीपों तक पहुंच प्रभावी रूप से पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, जो उसके रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भारत संसाधनों और प्रवासन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुप्ता ने कहा कि जिन क्षेत्रों में मजबूत बंदरगाह और व्यापारिक नेटवर्क रहे, वे ऐतिहासिक रूप से समृद्धि के केंद्र बने। उन्होंने कहा, ''अक्सर कहा जाता है कि जिन देशों में सबसे अधिक बंदरगाह होते हैं, वे सबसे समृद्ध बनते हैं, क्योंकि व्यापार और कारोबारी गतिविधियां उन्हीं के जरिए चलती हैं। वस्तुओं और व्यापार की आवाजाही के बिना समृद्धि संभव नहीं है।'' पूर्वी भारत की आर्थिक गिरावट पर चिंता जताते गुप्ता ने बिहार और ओडिशा के विकास मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद इन राज्यों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि असम और पूर्वोत्तर लंबे समय तक भौगोलिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग रहे। उन्होंने कहा, ''बिहार की स्थिति देखिए। अगर कुछ समय के लिए ओडिशा की खदानों और प्राकृतिक संसाधनों को अलग कर दें, तो उसकी अर्थव्यवस्था में क्या बचता है?

बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक फैसला होगा : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को राज्य की अपनी आईपीएल टीम बनाने को लेकर ''सकारात्मक फैसला'' होने का भरोसा जताया। उन्होंने यह टिप्पणी सोशल साइट 'एक्स' पर की।

मुख्यमंत्री बिहार से ताल्लुक रखने वाले वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की एक पोस्ट का जवाब देते हुए यह बात कही। अग्रवाल ने लिखा, ''क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की भी अपनी टीम होनी चाहिए, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन और कोलकाता नाईट राइडर्स हैं? बिहार की धरती ने देश को कई बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं।'' उनका सपना और प्रयास है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अग्रवाल ने कहा, ''मुझे पूरा

विश्वास है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो बिहार से निकलने वाली टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन सकती है।'' उन्होंने बिहार की क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ''बिना शर्त समर्थन'' देने का भी वादा किया और कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य की प्रतिभा मैदान पर चमके। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, ''मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं। बिहार की क्रिकेट 'भावना' के लिए सरकार स्पष्ट 'दृष्टिकोण' के साथ 'मिशन मोड' में कार्यरत है। आपके सहयोग से बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।''

जे-टीईटी में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे : राधा कृष्ण किशोर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रांची/भाषा। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जे-टीईटी) में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। मंत्री ने यह बात पांच सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के बाद कही। सरकार ने हाल ही में परीक्षा में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को शामिल करने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

किशोर ने कहा, जे-टीईटी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं, खासकर भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने को लेकर समिति की दूसरी बैठक आज हुई। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और एक-दो दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके बाद वह अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि भोजपुरी, मगही और अंगिका के साथ-साथ जनजातीय भाषाओं को भी सम्मान मिले। इस बीच सूत्रों ने बताया कि समिति की बैठक में इस मुद्दे पर मतभेद के कारण आम सहमति नहीं बन सकी।

समिति में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो मंत्रियों ने इस पर अलग राय जताई। समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई थी। इससे पहले 28 अप्रैल को मंत्रिमंडल ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को पश्च प्रभाव से मंजूरी दी थी। जे-टीईटी पात्रता परीक्षा नियमावली में विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषाओं से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर किए जाने को लेकर बढ़ते विरोध के बीच इस महीने की शुरुआत में पांच सदस्यीय मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था।

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का तबादला किया तथा कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, 2004 बैच के आईएएस अधिकारी और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार 2007 बैच के आईएएस अधिकारी तथा वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग में सतर्कता आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई से पुलिस पर हमले बढ़े, जवाबी फायरिंग करनी पड़ रही'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के कारण पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करनी पड़ रही है।

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी-कानून व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि बिहार पुलिस जाति के आधार पर मुठभेड़ नहीं करती है। उन्होंने कहा, पुलिस की कोई जाति नहीं होती और अपराधियों की भी कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे,

उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी, त्वरित सुनवाई और अपराध से अर्जित संपत्तियों की जब्ती जैसी कार्रवाई के कारण अपराधियों पर दबाव बढ़ा है, इसलिए कुछ लोग पुलिस पर हमला करने जैसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे निपटने के लिए तैयार है। एडीजीपी ने बताया कि बिहार पुलिस ने जनवरी से 15 मई तक अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने से जुड़े प्रावधानों के तहत 1,433 अपराधियों की पहचान की है और 428 लोगों के खिलाफ अदालतों में प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने बताया कि 103 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया जारी है, जबकि चार अन्य के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किए गए हैं।

सुधांशु कुमार ने कहा कि जनवरी से 15 मई तक हत्या के 2,023, डकैती के 311, लूट के 573 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार से जुड़े 1,572 मामलों समेत गंभीर अपराधों में कुल 33,126 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी में बाढ़ से तबाही, कई पुल और घर क्षतिग्रस्त

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के कारण कई महत्वपूर्ण पुल बह गए, घरों को नुकसान पहुंचा और कई गांवों में संपर्क बाधित हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक परामर्श जारी कर लोगों से नदियों में मछली पकड़ने या अन्य गतिविधियों के लिए जाने से बचने की अपील की है, क्योंकि आगे और बारिश का अनुमान जताया गया है।

अधिकारियों के अनुसार बह गए पुलों में निंगपिंग गांव के पास न्योकोरो स्थित आरसीसी पुल और गीबा मुख्यालय को लॉन्गटे गांव से जोड़ने वाला एक अन्य पुल भी शामिल है। निंगपिंग गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण सात कच्चे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कृषि भूमि, पशुधन और अन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। इस बीच, यहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को ऊपरी सुबनसिरी, कमले, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, निचला सुबनसिरी, सियांग बेल्ट और आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर रविवार को अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। इसी तरह की मौसम स्थिति मंगलवार तक जारी रहने का अनुमान है।

विनेश को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूएफआई को फटकार लगाई

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मशहूर महिला पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 'अयोग्य' घोषित करने के फैसले के लिए शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई और कहा कि वह इस पर आदेश देगा कि वह आने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में शामिल हो सकती हैं या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई का शीर्ष खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति देने की पूर्व प्रथा पर नहीं चलना 'बहुत कुछ कहता है'। विनेश मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करना चाहती हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देश में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है और संघ को 'प्रतिशोध' की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। भले ही डब्ल्यूएफआई के वकील ने यह साफ किया कि चयन के नियम मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली खिलाड़ियों को बाहर करने के लिए नहीं हैं और इस मामले में दिक्कत फोगाट के संन्यास लेने के फैसले से पैदा हुई थी। फिर भी अदालत ने टिप्पणी की कि डब्ल्यूएफआई की नीति का नतीजा यह हुआ कि उन्हें बाहर कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अगर वह मां नहीं बनी होतीं तो वह हिस्सा ले पातीं और योग्य हो जातीं। साथ ही अदालत ने यह भी जोड़ा कि एक खिलाड़ी को मुकदमों पर नहीं, बल्कि अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि अगर फोगाट ट्रायल में सफल होती हैं तो भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) द्वारा तय किए गए नियमों के तहत योग्यता के नियमों में ढील दी जा सकती है, ताकि एशियाई खेलों में उनके हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो सके। हालांकि वकील ने यह भी साफ किया कि चयन ट्रायल में उनके हिस्सा लेने के लिए योग्यता के नियमों में ढील डब्ल्यूएफआई को ही देनी होगी। उन्होंने कहा कि ट्रायल डब्ल्यूएफआई की एक तकनीकी टीम की देखरेख में, केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा चुने गए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में करवाए जा सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

नगालैंड में 'जन भागीदारी अभियान' शुरू किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोहिमा/भाषा। केंद्र का 'जन भागीदारी अभियान- सबसे दूर, सबसे पहले' शुक्रवार को नगालैंड में शुरू किया गया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। 'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और आवश्यक सेवाएं सबसे दूरस्थ क्षेत्रों और वंचित समुदायों तक पहुंचें। यह अभियान कोहिमा जिले में शुरू किया गया।

उपायुक्त बी हेनोक बुचेम ने कहा कि यह पहल समावेशी शासन और सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 'सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नगालैंड की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता शासन और सेवा वितरण में चुनौतियां पेश करती हैं और इसलिए, यह अभियान सरकारी सेवाओं को सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचाकर प्रशासन और लोगों के बीच संबंध को मजबूत करने का प्रयास करता है ताकि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए। जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए, बुचेम ने कहा कि विकास तभी सार्थक होता है जब नागरिक सक्रिय हितधारक बनते हैं। यह अभियान केवल योजनाओं के कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भरोसा कायम करना, जनता की शिकायतों को सुनना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

विरोध प्रदर्शन — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सीआईटीयू से संबद्ध पश्चिम बंगाल रेलवे हॉकर यूनियन से जुड़े फेरीवालों ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों से हटाये जाने के विरोध में कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। रेलवे अधिकारी पुलिस की सहायता से हावड़ा और सियालदह समेत विभिन्न स्टेशनों पर अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहे हैं। यूनियन ने दावा किया कि फेरीवालों की आजीविका छिन गई है। इसने फेरीवालों के पुनर्वास की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म और आसपास के अन्य क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने फेरीवालों को हटाने का कदम उठाया है।

विजय शंकर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय हरफनमौला विजय शंकर ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से शुक्रवार को संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि वह 'क्रिकेट खेलना' जारी रखने के लिए 'नए अवसरों की तलाश' करेंगे।

तमिलनाडु के 35 वर्षीय शंकर ने 2025-26 सत्र में त्रिपुरा टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2018 से 2019 के बीच भारत के लिए 12 वनडे और नौ टी20 मैच खेले। शंकर ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, क्रिकेट मेरी जिंदगी है। मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 25 साल बाद हर स्तर पर और

उच्चतम स्तर तक खेलने के लिए आभारी और धन्य महसूस करता हूं। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे सबसे गौरवपूर्ण और खुशी के पलों में से एक रहेगा। उन्होंने कहा, मैंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है ताकि नए अवसरों की तलाश कर सकूं और क्रिकेट खेलना जारी रख सकूं। बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। नागपुर में भारत के 500वें वनडे में आखिरी ओवर फेंकना और 2019 विश्व कप में पहली गेंद पर पहला विकेट लेना मेरे लिए अविस्मरणीय पल हैं। शंकर 2019 में वनडे विश्व कप टीम का हिस्सा भी थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। पैर के अंगूठे की चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और फिर वह टीम में वापसी नहीं कर सके। आईपीएल में शंकर ने चार टीमों का प्रतिनिधित्व किया। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स (2014 और 2025), सनराइजर्स हैदराबाद (2017, 2019-2021), दिल्ली कैपिटल्स (2018) और गुजरात टाइटन्स (2022-2024) शामिल है। वह मौजूदा सत्र में वह किसी टीम का हिस्सा नहीं थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शंकर ने 2012 में अपने पदार्पण के बाद कुल 77 प्रथम श्रेणी, 112 लिस्ट ए और 159 टी20 मैच खेले।

सुविचार

सेवा का असली आनंद वही है, जहाँ कोई स्वार्थ न हो, बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म ही महान होता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

व्यवस्था में सुधार से बनेगा विकसित भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जिन सुधारों पर जोर दिया है, वे आज अत्यंत प्रासंगिक हैं। लोग खुशहाल हों, उनका जीवन आसान हो, इसके लिए व्यवस्था में तेजी से कई सुधार करने होंगे। सबसे पहले, सरकारी सेवाओं को आसान बनाने की जरूरत है। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। चाहे जन्म प्रमाणपत्र लेना हो या बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना हो, सारे काम घर बैठे हो जाएं। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएं और जो शुल्क हो, वह ऑनलाइन ही जमा हो। काम पूरा होने की अवधि निश्चित कर दी जाए। कोई कर्मचारी अनुचित तरीके से फाइल को रोके तो उससे जवाब मांगा जाए। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी सेवाओं में एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। पिछले एक दशक में सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इस पर जोरदार प्रहार करना चाहिए। भारत में न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। इसमें बहुत संसाधन खर्च होते हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने की जरूरत है। छोटे विवादों, यातायात संबंधी मामलों, किराया विवादों, छोटे व्यापारिक विवादों आदि का ऑनलाइन निपटारा किया जाए। हर छोटे विवाद को अदालत में भेजने के बजाय स्थानीय मध्यस्थता से सुलझाया जाए। पुलिस प्रणाली में तो ढेरों सुधार करने की जरूरत है। भारत में आम आदमी पुलिस से मदद मांगने से डरता है। अगर उसे थाने जाना हो तो वह ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाना चाहता है, जिसकी वहां जान-पहचान हो। ऑनलाइन एफआईआर से लेकर शिकायत ट्रैकिंग, फोरेंसिक ढांचे में बड़े सुधार करने होंगे। आम जनता को सताने वाले, रिश्वत लेने वाले और अपने कृत्यों से पुलिस बल की छवि पर दाग लगाने वाले कर्मियों को सिर्फ निलंबित न किया जाए। निलंबन कोई सजा नहीं है। उन्हें बर्खास्त कर जेल भेजा जाए।

पिछले चार दशकों में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से कौशल विकास नहीं हुआ है। विद्यार्थी किताबें खूब पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं में अच्छे अंक ला रहे हैं। फिर भी रोजगार से वंचित हैं। हर साल बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब शिक्षा को कौशल से जोड़ने की जरूरत है। विद्यार्थियों को वह सिखाएं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। जो जानकारी सिर्फ बस्ते का बोझ बढ़ाए और जीवन में कोई काम न आए, उसे या तो हटाएं या सीमित करें। कोरोना महामारी के बाद लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का महत्त्व समझ में आ रहा है। इस मामले में सरकार को दो स्तर पर काम करना होगा। सबसे पहले तो चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाएं। जिन बीमारियों में सिर्फ परामर्श और दवाइयों की जरूरत होती है, उनके इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़ें। ऐसे मरीजों को ऑनलाइन वीडियो के जरिए परामर्श मिले। अगर कोई जांच करानी हो तो वह लिख दी जाए। उसकी रिपोर्ट डॉक्टर ऑनलाइन देखकर दवाइयां बताएं और परामर्श दें। इससे अस्पतालों पर दबाव काफी कम हो सकता है। सरकार हर गांव और शहर में जनसहयोग से बगीचे विकसित करने पर जोर दे। लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे सुबह-शाम सैर करें। उन्हें योग, प्राणायाम, व्यायाम, खेलकूद और पोषक तत्त्वों के बारे में जानकारी दी जाए। इससे वे कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा माहौल बनाया जाए, जिसमें लोग अच्छी आदतें अपनाने के लिए आगे आएं। उन्हें लगना चाहिए कि अच्छा नागरिक बनने के बहुत फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति यातायात के सभी नियमों का पालन करे, समय पर पानी-बिजली के बिल जमा कराए, समय पर सभी करों का भुगतान करे, हमेशा टिकट लेकर यात्रा करे... उसे ईंधन खरीद से लेकर विभिन्न योजनाओं तक विशेष छूट मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग अच्छाई की ओर कदम बढ़ाएंगे, वे उतनी जल्दी विकसित भारत का निर्माण करेंगे।

ट्वीटर टॉक

दिल्ली में प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडौलिडेस से मिलकर खुशी हुई। हमने इंडिया-साइप्रस दोस्ती को और मज़बूत करने पर अच्छी तरह बातचीत की। हमारे देशों के बीच करीबी रिश्तों को देखते हुए, हमने अपनी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का फ़ैसला किया है।

-नरेन्द्र मोदी

राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व अखिल भारतीय सहकार्यवाहिका, अदारनिया रुक्मणी अक्का जी के निधन की खबर बहुत दुखद और दिल दहला देने वाली है।ङ्ङभारत माता की सेवा, महिला शक्ति के जागरण और संगठन निर्माण के लिए समर्पित उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है।

-दिया कुमारी

कोटा से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। सरकारी लापरवाही की वजह से श्री रामेश्वर रावल की जान जाने की खबर बहुत दुखद है। यह और भी दुखद है कि इगझ सरकार में इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

वचन और मित्रता

अलबर्ट आइंस्टीन की संगीतकार लियोपोल्ड गोदोव्सिकी के साथ प्रगाढ़ मैत्री थी। एक दिन गोदोव्सिकी ने आइंस्टीन से कहा, 'प्रिय, मेरा नाई तुमसे मिलने के लिए बेहद लालायित है।' आइंस्टीन ने उत्तर दिया, 'बंधु, मैं इसी घड़ी तुम्हारे साथ उसकी दुकान पर चलता, लेकिन जल्दी में हूं। तुम मुझे उसका पता दे दो। कभी उससे मिल लूंगा। आइंस्टीन ने नाई का पता जेब में रखा और चले गए। काफी वक्त बीत गया। आइंस्टीन को न्यूयार्क जाने का समय ही नहीं मिला, पर 'भुलक्कड़' के रूप में प्रख्यात होने के बावजूद वे नाई से मिलने का अपना वादा कभी नहीं भूले। एक दिन उन्हें खबर मिली कि गोदोव्सिकी चल बसे। फलतः उन्हें न्यूयार्क जाना पड़ा और गोदोव्सिकी के परिवार को सांत्वना बंधाने के बाद आइंस्टीन ने जो पहला काम किया, वह उस नाई से भेंट का था। इस बीच नाई गोदोव्सिकी के साथ हुई अपनी बात को कभी का भूल चुका था। उसने सोचा, इतने महान वैज्ञानिक भला उसकी दुकान पर क्योंकर आयेंगे। लेकिन जब उस दिन उसने यकायक आइंस्टीन को अपनी दुकान पर आया देखा तो मारे खुशी के उसकी आंखें छलछला आयीं तथा भावावेश से उसका गला रुंध गया। वह आइंस्टीन को एकटक ताकता ही रह गया।

सामयिक

प्रधानमंत्री की अपील समय पूर्व सुरक्षोपाय

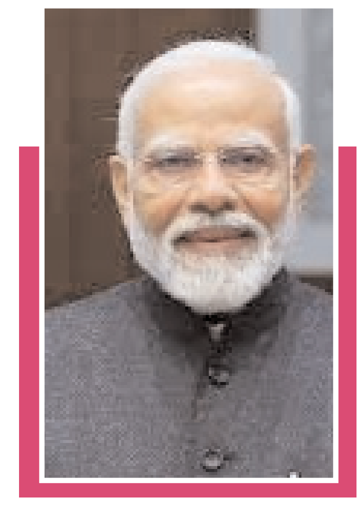

जहां तक तेलों के दाम बढ़ाने की बात है तो दुनिया में कौन देश है जहां दाम नहीं बढ़े? तेल कंपनियां प्रतिदिन करीब एक हजार करोड़ रुपये का घाटा उठा रही हैं। सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये शुल्क घटा चुकी है। खाद की की 2200 रुपये की बोरी 242 रुपये में मिल रही है। लगभग 82 देशों में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग हो रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत महंगा हो चुका है। भारत में इसे नियंत्रित रखा गया है। विरोधियों की प्रतिक्रियाएं जैसी भी हो आम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि जब वैश्विक संकट है तो दाम बढ़ेंगे ही और अनेक कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे यह कम है।

अवधेश कुमार
मोबाइल -9811027208

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के हर संभव न्यूनतम उपयोग के साथ अन्य अपीलों व कदमों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में आलोचना व विरोध के स्वर ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने 10 मई को देशवासियों से मुख्यतः तीन अपील की- एक साल तक सोने की खरीद टालने, गैर जरूरी विदेश यात्राएं न करने और पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग व सार्वजनिक यातायात का ज्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। थोड़े शब्दों में कहें तो इनका उद्देश्य बढ़ते वैश्विक संकट से सामना करने के लिए देश को तैयार करना है। हालांकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा जा रहा है कि चुनाव तक प्रधानमंत्री को संकट नहीं दिखा और अचानक दिख गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो आरोप यह है कि बस केवल चुनाव तक रोका गया था। इस तरह की अनेक आलोचनायें हो रहीं हैं और होती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने अपील के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में जाते समय अपने काफिले को कम किया तथा केवल दो गाड़ियां दिखाई थी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अन्य मंत्रियों ने भी अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम की। इसके बाद पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें और निर्णय आए जहां भाजपा सरकारों के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या में कटौती की, स्वयं तथा सरकारी अधिकारियों के कार्यालय जाने की व्यवस्था में बदलाव किया और कई जगह सप्ताह में निश्चित दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति दी गई। इस तरह के कदमों से कई बार आशंका पैदा होती है मानो देश गंभीर संकट में है और लोगों से मितव्ययिता यानी कम खर्च करने को कहा जा रहा हो। विरोध और प्रतिक्रियाएं भी संदेहों को बढ़ावा देतीं हैं।

वस्तुतः विरोध व आलोचनाएं राजनीतिक ज्यादा हैं। कुछ गलतफहमियां भी पैदा की जा रहीं हैं। यह केवल विदेशी मुद्रा वाले खर्च में कमी करने संबंधी अपील है। देश के अंदर मितव्ययिता की अपील प्रधानमंत्री ने नहीं की। फिर प्रधानमंत्री ने अपील किया है, कोई नियम-कानून नहीं बना है कि जिससे न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। दूसरे, इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े संकट में है। प्रधानमंत्री की अपील में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल की भी बात है। सरकार आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार इस तरह की बातें कर रही है। पूरी अपील को साथ मिलकर देखने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति संतोषजनक है। विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 690 अरब डॉलर है जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। महंगाई थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नियंत्रण में है। किंतु भारत एक बड़ा आयातक देश है। हम कच्चे तेल का 89% के आसपास आयात करते हैं तो सोने का 90% से ज्यादा। हमारे कुल आयात बिल में चार मदों में सबसे ज्यादा खर्च हैं। कच्चा तेल पर 2025- 26 में कुल 134.7 अरब डॉलर का खर्च आया तो सोना पर 72 अरब डॉलर , खाने के तेल पर 19.5 अरब डॉलर और उर्वरक पर 14.5 अरब डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान सुरक्षा की गारंटी होती है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल पैदा किया है। हार्मूज संकट ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों के लिए समस्या पैदा किया है जिसका समाधान नहीं हो रहा। युद्ध कब समाप्त होगा क्या मोड़ लेगा कहना कठिन है। यूक्रेन युद्ध 4 वर्षों से चल रहा है। पश्चिम एशिया में गाजा का संकट भी समाप्त नहीं हुआ है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक समाप्त हो सकता है। यूरोप अमेरिका मतभेद के कारण नाटो का अस्तित्व संकट में है। कोई वैश्विक संस्था इतनी प्रभावी नहीं जो व्यापार से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों, समुद्री परिचालन आदि के अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करा सके। पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला बाधित ही नहीं है उथल-पुथल के दौर में है। खाड़ी का संकट बहु-आयामी वृहद आर्थिक चुनौती पैदा करता है। अभी तक आयात पर खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा की काफी हद तक भरपाई निर्यात तथा रेमिटेंस यानी विदेश में कार्यरत या रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए विदेशी मुद्रा से हो जाता था। इस कारण चालू खाते का घाटा हमेशा नियंत्रण में रहा। वर्ष 2024 में विदेशी में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन की मात्रा 138 अरब डालर थी। अप्रैल से सितंबर 2025 तक यह पिछले वर्ष के 64.7 अरब डॉलर से बढ़कर 73 अरब डालर हो गया था। खाड़ी युद्ध और वैश्विक संकट के कारण इसमें व्यापक कमी की संभावना पैदा हो गई है। इसी तरह वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं) 4.22% बढ़कर 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जबकि आयात लगभग 6.5% की वृद्धि के साथ 979 अरब डॉलर तक पहुंचा। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। किंतु मूल्य बढ़ते रहने के बावजूद आवश्यक आयातों को रोकना संभव नहीं । अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो वित्त वर्ष 2026 में चालू खाते का घाट सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में 2.2 प्रतिशत तक जा सकता है। यह करीब 84.5 अरब डॉलर हो सकता है। यह मोटा- मोटी घाटे में तीन गुनी वृद्धि होगी।

ऐसे संकटग्रस्त दुनिया में आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा समय पूर्व करने से ही भविष्य की निश्चिंतता हो सकती है। कच्चे तेल के दाम 26 फरवरी के 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष हमने 11 लाख 40 हजार करोड़ का तेल आयात किया तथा 6 लाख 50 हजार करोड़ के आसपास का सोना। इस वर्ष तेल का आयात बिल 17 लाख करोड़ और सोने का 10 लाख करोड़ हो सकता है।पिछले वर्ष हमने लगभग 470 टन सोना आयात किया। अगर 1 वर्ष तक सोना न खरीदें तो तूफान नहीं आ जाएगा। इनमें 50% गिरावट आ गई तो 35-36 अरब डॉलर बचते हैं। अगर आप पेट्रोल डीजल में 20% की भी कटौती कर लेते हैं तो यह भी 35 - 36 अरब डालर हो जाता है। विदेश यात्राएं करने वालों में बड़ी संख्या उनकी है जो घूमने - फिरने, मौज -मस्ती या आराम के लिए जाते हैं। इनको एक वर्ष के लिए टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष विदेश में शादियों की प्रवृत्ति कम करने के लिए देश में शादी करने की अपील की थी। वे भारत में तीर्थ और पर्यटन स्थलों के स्वयं प्रचार करते रहे हैं ताकि देश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन की प्रवृत्ति बढ़े। ये ऐसी बातें हैं जिनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए।

जहां तक तेलों के दाम बढ़ाने की बात है तो दुनिया में कौन देश है जहां दाम नहीं बढ़े? तेल कंपनियां प्रतिदिन करीब एक हजार करोड़ रुपये का घाटा उठा रही हैं। सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये शुल्क घटा चुकी है। खाद की की 2200 रुपये की बोरी 242 रुपये में मिल रही है। लगभग 82 देशों में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग हो रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल 50 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत महंगा हो चुका है। भारत में इसे नियंत्रित रखा गया है। विरोधियों की प्रतिक्रियाएं जैसी भी हो आम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि जब वैश्विक संकट है तो दाम बढ़ेंगे ही और अनेक कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे यह कम है। इसका अर्थ हुआ आम लोग इसके लिए तैयार हैं।

तो जिनके पास धन है वे अपने पर नियंत्रण रखें। सोने की खरीद और अनावश्यक विदेश की यात्राएं कुछ समय के लिए टालें। विदेशी मुद्रा भविष्य की चुनौतियों के बीच सुरक्षा की गारंटी है। आवश्यक आपूर्ति की गारंटी विदेशी मुद्रा ही देती है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के कारण प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सरकार को 67 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर 2000 करोड डॉलर का कर्ज लेना पड़ा था। उसके बाद नरसिंह राव सरकार को भी 45 दिनों में करीब 47 टन सोना और गिरवी रखना पड़ा ताकि भारत 4000 करोड डॉलर कर्ज प्राप्त कर सके और आयात बिल का भुगतान संभव हो। वैसी नौबत फिर न आये इसलिए आवश्यक है कि वैश्विक परिस्थितियों को समझते हुए देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री की अपील माने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे।

नजरिया

तपती धरती, झुलसता जीवन : 'हीट-वेव' की चुनौती

ललित गर्ग
मोबाइल : 9811051133

वर्ष 2026 की गर्मी केवल एक मौसमीय घटना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अप्रैल-मई के दौरान भारत सहित दक्षिण एशिया के अनेक हिस्सों में पड़ी रिकॉर्ड हीटवेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का संकट नहीं, वर्तमान की भयावह वास्तविकता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई शहरों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें सूनी दिखने लगीं, श्रमिकों का श्रम ठहरने लगा और बच्चों, बुजुर्गों तथा गरीब तबकों के सामने जीवन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। यह संकट अचानक नहीं आया। यह दशकों से प्रकृति के साथ किए गए असंतुलित व्यवहार, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई, संसाधनों के दोहन और सुविधावादी जीवनशैली का परिणाम है। प्रकृति ने बार-बार संकेत दिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उन संकेतों को अनसुना किया। आज वही उपेक्षित चेतावनियां लू बनकर हमारे सामने खड़ी हैं।

हीटवेव का सबसे बड़ा कारण केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि वह विकास मॉडल है जिसने धरती की प्राकृतिक ढाल को कमजोर कर दिया। जंगल सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण को शीतल रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन विडंबना है कि विकास के नाम पर जंगलों का तेजी से विनाश हुआ। हर वर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ा, नमी कम हुई, वर्षा चक्र प्रभावित हुआ और गर्म हवाओं की अवधि लंबी होती गई। आज शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। महानगरों में हरित क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट, डामर और शीशे की ऊंची इमारतें ले रही हैं। इससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ा है। शहर अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो चुके हैं। कंक्रीट दिनभर सूर्य की ऊष्मा को सोखता है और रात में धीरे-धीरे छोड़ता है। परिणामस्वरूप रातें भी गर्म होती जा रही हैं और शरीर को राहत नहीं मिल पाती।

दिल्ली, मुंबई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में रात का तापमान पहले की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। गरीब बस्तियों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां न हरित क्षेत्र हैं, न पर्याप्त जल आपूर्ति, न शीतलन के साधन। टीन की छतों वाले घर दिन में भट्ठी बन जाते हैं। गर्मी की मार सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। अमीर वर्ग एयर कंडीशनर और बंद कमरों में राहत खोज लेता है, लेकिन मजदूर, रिक्शाचालक, रेहड़ी वाले और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक खुले आसमान के नीचे झुलसते रहते हैं। विडंबना यह भी है कि गर्मी से राहत का सबसे लोकप्रिय साधन एयर कंडीशनर स्वयं संकट को बढ़ाने वाला कारक बनता जा रहा है। एक एयर कंडीशनर कमरे को ठंडा करता है, लेकिन बाहर उतनी ही गर्म हवा छोड़ता है। इसके साथ ही बिजली की खपत बढ़ती है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला आधारित ऊर्जा से आता है। रेफ्रिजरेंट गैसें अतिरिक्त ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र निर्मित हो गया है-गर्मी बढ़ती है, एसी बढ़ते हैं, उत्सर्जन बढ़ता है और फिर गर्मी और बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर डाल रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि बढ़ती गर्मी और अनिश्चित मौसम के कारण गेहूं, धान और अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। गर्म हवाएं पौधों की वृद्धि रोकती हैं, जल स्रोतों को सुखाती हैं और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में खाद्य संकट भी गहरा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इसका गंभीर प्रभाव दिख रहा है। लू लगना, निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को है।

गर्मी का यह संकट सामाजिक और मानवीय संकट भी बन सकता है। जल स्रोतों के सूखने, कृषि संकट और जीवन परिस्थितियों के बिगड़ने से बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ सकता है। जैव विविधता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अनेक जीव-जंतु और वनस्पतियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं। हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

केवल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी करना पर्याप्त नहीं है। हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख विषय के रूप में स्वीकार करते हुए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। सबसे पहले शहरों में हीट एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। प्रत्येक शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण, छायादार मार्ग, सार्वजनिक प्याऊ और शीतलन केंद्रों की व्यवस्था आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों के समय निर्धारण में क्षेत्रीय तापमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीखी दोपहर में श्रमिकों के लिए कार्यावधि सीमित की जाए और उनके लिए विश्राम तथा पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य हो।

सरकार को भवन निर्माण नीति में भी परिवर्तन लाना होगा। पारंपरिक भारतीय वास्तुकला-हवादार घर, आंगन, मिट्टी आधारित निर्माण, हरित छतें और प्राकृतिक वेंटिलेशन को बढ़ावा देना चाहिए। कांच की चमचमाती इमारतों और ऊष्मा अवशोषित करने वाले निर्माणों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। कूल रूफ तकनीक, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा आधारित शीतलन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वन संरक्षण और वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं, राष्ट्रीय प्राथमिकता बनना चाहिए। शहरों में माइक्रो फॉरेस्ट, पार्क और हरित गलियारों का निर्माण किया जाए। जल निकायों और पारंपरिक तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए क्योंकि वे स्थानीय तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन केवल सरकारें यह लड़ाई नहीं जीत सकतीं। आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। हमें उपभोगवादी जीवनशैली पर पुनर्विचार करना होगा। पानी का संयमित उपयोग, ऊर्जा की बचत, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और स्थानीय पर्यावरण संरक्षण अब व्यक्तिगत विकल्प नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हैं।

भारतीय समाज में कभी सार्वजनिक प्याऊ, छायादार विश्राम स्थल और जल सेवा की समृद्ध परंपरा थी। गर्मियों में राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था पुण्य कार्य माना जाता था। आज उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। समाज, धार्मिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन मिलकर जल सेवा और राहत कार्यों का अभियान चला सकते हैं। गर्मी और जल संकट को राजनीति का विषय बनाने के बजाय सहयोग और समाधान का विषय बनाना होगा। जल विवादों और संसाधनों पर स्वार्थपूर्ण राजनीति भविष्य को और कठिन बनाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन को राष्ट्रीय सहमति का विषय बनाया जाए।

वर्ष 2026 की यह झुलसाती गर्मी हमें चेतावनी दे रही है कि यदि हमने अभी भी प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित नहीं किया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और विकराल होगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जैव विविधता नष्ट होगी, खाद्य संकट गहराएगा और मानव जीवन अधिक कठिन हो जाएगा। यह समय प्रकृति से संघर्ष का नहीं, उसके साथ सामंजस्य का है। हमें विकास की ऐसी दिशा चुननी होगी जिसमें पर्यावरण, मानव जीवन और भविष्य सुरक्षित रह सके। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सूरज की तपिश केवल असुविधा नहीं, अस्तित्व का संकट बन जाएगी।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर ट्रंप के बदले रुख से नाटो सहयोगी हैरान

हेलसिंगबोर्ग (स्वीडन)/एपी

यूरोप से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश देने के महज कुछ ही सप्ताह बाद पोलैंड में इतने ही सैनिक भेजने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर नाटो सहयोगियों और रक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को हैरानी जताई है।

स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया माल्मेर स्टेनरगार्ड ने नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान संवाददाताओं से कहा, यह वास्तव में भ्रमित करने वाला है और इस स्थिति से निपटना हमेशा आसान नहीं होता। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी शामिल थे।

इस फैसले से खुद अमेरिकी रक्षा अधिकारी भी असमंजस में हैं। नाम न छापने की शर्त पर संवेदनशील सैन्य मामलों पर चर्चा करने वाले दो अधिकारियों में से एक ने कहा, हमने पिछले दो सप्ताह का अधिकांश समय पहली घोषणा (सैनिकों की वापसी) के बाद की तैयारियों में बिताया है। हमें भी नहीं पता कि इस नए फैसले का क्या मतलब है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नाव्रोकी के साथ उनके मजबूत संबंधों के कारण लिया गया है, जिनका ट्रंप ने पिछले साल के चुनावों में समर्थन किया था। ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के बजाय कम करने के हफ्तों के विरोधाभासी बयानों के बाद राष्ट्रपति का यह बदला हुआ रुख सामने आया है।

सैनिकों की तैनाती को लेकर समन्वय बनाए रखने के अमेरिकी वादे के बावजूद नाटो सहयोगियों को इस फैसले की भनक तक नहीं लगी। इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि वह यूरोप में सैनिकों की संख्या में लगभग 5,000 की कटौती कर रहा है, और अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि लगभग 4,000 सैनिकों को अब पोलैंड नहीं भेजा जा रहा है।

अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में 'थाड' के लगभग आधे भंडार का इस्तेमाल किया : अमेरिकी मीडिया

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल की रक्षा करते हुए मिसाइल रोधी अपनी उन्नत रक्षा प्रणाली 'थाड' के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने यह खबर दी। 'द पोस्ट' ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करते हुए 200 से अधिक 'टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (थाड) अवरोधक दागे जो अमेरिका के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा है। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में नौसैनिक पोतों से 100 से अधिक 'स्टैंडर्ड मिसाइल-3' और 'स्टैंडर्ड मिसाइल-6' अवरोधक दागे गए।

'द पोस्ट' की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल ने अपने 100 से कम 'एरो' अवरोधक और लगभग 90 'डेविड्स स्लिंग' अवरोधक दागे जिनमें से कुछ अवरोधकों का इस्तेमाल यमन और लेबनान में ईरान समर्थित समूहों द्वारा दागे गए कम उन्नत प्रक्षेपास्त्रों के खिलाफ किया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 28 फरवरी को हमले करते हुए उसके साथ युद्ध शुरू किया था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई समेत उसके कई अहम नेताओं की मौत हो गई।

इसके जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले किए। दोनों पक्षों के बीच आठ अप्रैल को अस्थायी संघर्षविराम लागू हुआ। इसके बाद से अमेरिका और ईरान चार दशक से अधिक समय से जारी शत्रुता को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, ''अमेरिका ने कुल लगभग 120 अधिक अवरोधक दागे।'' एक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के अनुसार अमेरिका और इजराइल आगामी दिनों में ईरान के खिलाफ फिर से हमले शुरू करते हैं तो अमेरिकी सेना द्वारा और अधिक अवरोधकों का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है क्योंकि इजराइली सेना ने हाल में अपनी कुछ मिसाइल-रक्षा बैटरियों को रखरखाव के लिए बंद करने का फैसला किया है।

अधिकारी ने कहा, ''अगर हमले फिर शुरू होते हैं तो यह असंतुलन और बढ़ सकता है।''

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने एक बयान जारी कर इजराइल और अमेरिका के बीच इस्तेमाल किए गए सैन्य संसाधनों के संतुलन का बचाव किया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने 'द पोस्ट' से कहा, ''ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' के दौरान इजराइल और अमेरिका, दोनों ने रक्षा का बोझ समान रूप से उठाया। इस अभियान में दोनों देशों ने लड़ाकू विमानों, मानव रहित विमान-रोधी प्रणालियों और अन्य विभिन्न उन्नत हवाई एवं मिसाइल-रक्षा क्षमताओं का अधिकतम प्रभावशीलता के साथ इस्तेमाल किया।

शेल्टर कहां, इंफ्रास्टक्चर कहां?, बेजुबानों के लिए सामने आईं सोनम बाजवा

चंडीगढ़/एजेन्सी

अभिनेत्री सोनम बाजवा ने स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से खास अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सोनम बाजवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के बड़े पैमाने पर सफाए का कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सीएम मान से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर फिर से विचार करें और बेजुबान जानवरों के प्रति दया और इंसानियत का रवैया अपनाएं। सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को एक साथ हटाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से नियमित रूप से हटाने की बात कही है, जिसमें स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और शेल्टरिंग शामिल है, न कि सड़कों से कुत्तों को पूरी तरह हटा देने की। अभिनेत्री ने सवाल उठाते हुए पूछा, शेल्टर कहां हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? उन्होंने कहा कि यह सिस्टम बेजुबान जानवरों के लिए मौत की सजा नहीं बन सकता। सोनम ने स्पष्ट किया कि पब्लिक सेफ्टी और इंसानी जिंदगी जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन दया और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। सोनम ने मुख्यमंत्री से दिल से गुजारिश की, प्लीज इस तरीके पर फिर से सोचें और इस मुद्दे में दया और इंसानियत वाला हल चुनें। सोनम ने सुझाव दिया कि सीएम भगवंत मान जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एनजीओ, पशु चिकित्सकों, स्थानीय अधिकारियों और पब्लिक सेफ्टी एक्सपर्ट्स को एक साथ बिठाकर एक व्यावहारिक, इंसानी और संवेदनशील समाधान निकालें। उन्होंने आगे लिखा, हम बेजुबानों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उससे आखिरकार पता चलता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं। बता दें कि स्ट्रे डॉग्स से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जिसके अनुसार, कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है।

कुमार सानू और बेटी शैनन लंदन में करेंगे ग्रैंड लाइव कॉन्सर्ट

मुंबई/एजेन्सी

हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की जब भी बात होती है, तो उसमें मशहूर गायक कुमार सानू का नाम जरूर लिया जाता है। 90 के दशक में अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले कुमार सानू आज भी दुनियाभर में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके गाए रोमांटिक गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। अब एक बार फिर वह अपने फैंस के लिए खास म्यूजिकल तोहफा लेकर आ रहे हैं। इस बार उनके साथ उनकी बेटी शैनन के. भी स्टेज साझा करेंगी। दोनों 25 मई 2026 को लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक ग्रैंड लाइव सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। यह कॉन्सर्ट सिर्फ पुराने और नए दौर के संगीत का खूबसूरत संगम माना जा रहा है। शो में बॉलीवुड के सदाबहार गानों को बड़े लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ पेश किया जाएगा। यहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के गानों का मेल देखने को मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम अलग-अलग पीढ़ियों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। कॉन्सर्ट को लेकर कुमार सानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आईएएनएस से कहा, ''इस सफर की शुरुआत फैंस की वजह से हुई। लोग लगातार मेरी बेटी शैनन के बारे में पूछते थे और उनके अंग्रेजी गानों को पसंद करते थे। इसी को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने शैनन को शो का हिस्सा बनाने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे सिर्फ दो कॉन्सर्ट में शामिल किया गया था ताकि यह देखा जा सके कि दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है।'' कुमार सानू ने कहा, ''जब शैनन ने स्टेज पर अंग्रेजी गानों पर परफॉर्म किया, तब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। इससे एहसास हुआ कि विदेशों में रहने वाले लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के संगीत से जुड़ाव महसूस करते हैं। शैनन के जुड़ने से 90 के दशक वाले शो में नई ताजगी आई।''

उन्होंने कहा, ''यह लगातार दूसरा साल है जब मैं इस तरह का म्यूजिकल टूर कर रहा हूं। इस दौरान मैंने पुराने दौर के कई यादगार गानों को फिर से मंच पर जीवंत किया। साधना सरगम 90 के दशक की बेहद प्रतिभाशाली गायिका हैं और उनके साथ मंच साझा करना हमेशा खास अनुभव रहता है।'' उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, ''शैनन में पुराने गानों को आधुनिक पॉप अंदाज में पेश करने की खास कला है। एक पिता के तौर पर मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि वह एक अच्छी कलाकार होने के साथ-साथ दूसरे कलाकारों का सम्मान करना भी जानती हैं।''

वहीं शैनन के ने भी इस टूर को अपने करियर का बेहद खास अनुभव बताया। उन्होंने कहा, ''अपने पिता और साधना सरगम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज सोशल मीडिया, रीमिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से नई पीढ़ी फिर से 90 के दशक के बॉलीवुड गानों को सुन रही है।'' साधना सरगम ने भी इस टूर को यादगार बताते हुए कहा, ''कुमार सानू के साथ फिर से पुराने गाने गाना बेहद शानदार अनुभव रहा। नई पीढ़ी को इन गानों का आनंद लेते देखना बहुत अच्छा लगता है।'' यह कॉन्सर्ट लंदन में रॉक ऑन म्यूजिक द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर जाना बेहद मुश्किल काम : रुबीना दिलैक

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री रुबीना दिलैक मां बनने के बाद करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रही हैं। उन्हें प्रोजेक्ट के काम से अक्सर घर से दूर जाना पड़ता है। इस बीच रुबीना ने अपने जुड़वां बच्चों से दूर रहने की भावनात्मक पीड़ा पर बात की। उन्होंने बताया कि बच्चों को घर पर छोड़कर जाना या उनसे दूर रहना बेहद मुश्किल काम है। रुबीना वर्तमान में रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हैं। आईएएनएस के साथ बातचीत में रुबीना ने बताया कि जब वह काम के सिलसिले में बाहर होती हैं तो वीडियो कॉल पर उनकी बेटियां रोते हुए मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ कहती हैं, जिसे सुनकर उनका दिल टूट जाता है। रुबीना भावुक होते हुए बोलीं, वीडियो कॉल तो होते रहते हैं, लेकिन शारीरिक अपनापन नहीं मिल पाता। उनकी वह आवाज सुनकर मेरा दिल पसीज जाता है।

रुबीना ने माना कि वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि मां बनने और करियर के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना पाऊंगी। मैं पूरी तरह तैयार भी नहीं हूं। असल में कोई भी आपको मां बनने के लिए पहले से तैयार नहीं करता। यह मेरी ही नहीं बल्कि हर कामकाजी मां की चुनौती है। भावनात्मक मुश्किलों के बावजूद रुबीना काम से जुड़े सपने को छोड़ना नहीं चाहतीं। उन्होंने बताया, इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़े सपने देखना बंद कर दें। मैं अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हूं और अपनी बेटियों को यह एहसास दिलाना चाहती हूं कि उनकी मम्मा ने अपने सपनों को उनके साथ रहते हुए ही पूरा किया।

अमृतसर में शुक्रवार को गर्मी के मौसम में अमृतसर, पंजाब में छात्र खुद को चिलचिलाती धूप से बचाते हुए।

'मीतू पंजाबी' बनकर छाईं आकांक्षा पुरी

मुंबई/एजेन्सी

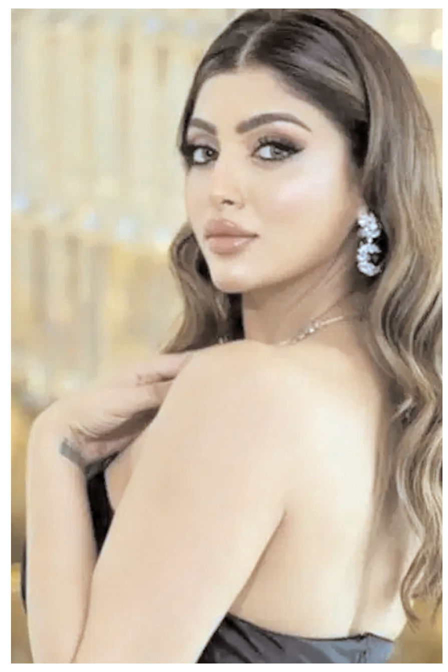

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों क्राइम और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज में अभिनेत्री अकांक्षा पुरी 'मीतू पंजाबी' नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पहले डांसर होती है और बाद में पुलिस की मुखबिर बन जाती है। उनके अभिनय की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। इस बीच आकांक्षा ने अपने किरदार, अभिनय अनुभव और रणदीप हुड्डा के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की। अकांक्षा पुरी ने कहा, ''मैं लंबे समय से कुछ अलग और चुनौतीपूर्ण करना चाहती थी। 'मीतू पंजाबी' का किरदार निडर, मजबूत और भावनात्मक रूप से काफी गहरा है। इस किरदार ने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका दिया। एक कलाकार के तौर पर मैंने अपने अंदर के मजबूत पहलू को इस किरदार के जरिए महसूस किया।'' आकांक्षा ने कहा, 'मीतू पंजाबी' मेरे अंदर कई तरह की भावनाएं लेकर आई। इस भूमिका को निभाने के लिए मुझे किरदार की भावनाओं को गहराई से समझना पड़ा। इस किरदार ने मुझे खुद का नया रूप खोजने का मौका दिया।''

अकांक्षा पुरी ने अपने सह-कलाकार रणदीप हुड्डा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''रणदीप हर सीन में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अभिनय करते हैं। उनके साथ काम करते समय खुद भी ज्यादा ध्यान और मेहनत के साथ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। वह अपने हर सीन में पूरी सच्चाई लेकर आते हैं। उनके साथ काम करना बेहद खास अनुभव रहा, क्योंकि उनके साथ अभिनय करते हुए आप खुद भी अपने काम में और ज्यादा डूब जाते हैं।'' वहीं सीरीज के निर्देशक नीरज पाठक ने भी रणदीप हुड्डा की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''रणदीप की मेहनत और काम के प्रति समर्पण देखकर अब मुझे दूसरे कलाकारों से भी वैसी ही उम्मीद होने लगी है।'' नीरज पाठक ने बातचीत के दौरान दिवंगत अभिनेता इरफान खान को भी याद किया। उन्होंने कहा, ''मेरा इरफान खान के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैंने उनके साथ दूरदर्शन के एक पुराने शो में काम किया था। उस दौरान मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा, उन्हें जरूर उसमें लूंगा।'' नीरज पाठक ने फिल्म 'राइट या रॉन्ग' बनाई थी, जिसमें सनी देओल और इरफान खान दोनों नजर आए थे।

सस्पेंस, कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरपूर होगी 'प्रीतम एंड पेड्रो'

मुंबई/एजेन्सी

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों अलग-अलग तरह की कहानियां दर्शकों को देखने को मिल रही हैं। अब एक नई सीरीज जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है, जिसका नाम है 'प्रीतम एंड पेड्रो'। इस सीरीज का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसने आते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खास बात यह है कि मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी का यह ओटीटी दुनिया में पहला बड़ा प्रोडक्शन है। टीजर में कॉमेडी के साथ रहस्य और कन्फ्यूजन का ऐसा मिश्रण दिखाया गया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। टीजर की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है, जहां सब कुछ थोड़ा अलग और मजेदार नजर आता है। कहानी में दो ऐसे किरदार दिखाई देते हैं जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हालात उन्हें साथ ले आते हैं। यही वजह है कि उनके बीच कई मजेदार और उलझन भरे पल देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ सब कुछ सामान्य दिखता है, वहीं दूसरी तरफ अचानक होने वाली घटनाएं कहानी को रहस्यमयी बना देती हैं। यही अंदाज दर्शकों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखता है। इस सीरीज में अरशद वारसी और वीर हिरानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। टीजर में दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी दिलचस्प नजर आ रही है।

इसके अलावा, शो में विक्रांत मैसी भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। उनका किरदार कहानी में रहस्य और सस्पेंस को बढ़ाता नजर आ रहा है, वहीं बोमन ईरानी और मोना सिंह भी सीरीज का हिस्सा हैं। टीजर में सभी कलाकारों की झलक भले ही कम दिखाई गई हो, लेकिन हर किरदार अपने अंदर कोई न कोई राज छिपाए हुए लगता है। इस शो का निर्देशन मशहूर निर्देशक अविनाश अरुण ने किया है। राजकुमार हिरानी और अविनाश अरुण की यह जोड़ी दर्शकों के लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आने वाली है। टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच शो को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग खास तौर पर अरशद वारसी और विक्रांत मैसी को एक साथ देखने को लेकर उत्साहित हैं। वहीं कई दर्शकों का मानना है कि राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ने से इस सीरीज से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। 'प्रीतम एंड पेड्रो' 3 जुलाई 2026 को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का टीज़र जल्द होगा रिलीज़

मुंबई/एजेन्सी

गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पोस्टर जारी करने के बाद, फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म का टीज़र जल्द रिलीज़ किया जाएगा। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े स्टारर यह सोशल-नेशनल ड्रामा अपनी दमदार थीम और प्रभावशाली विजुअल्स के चलते पहले ही चर्चा में आ चुका है। ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रस्तुत यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। फिल्म का निर्देशन चेतन डीके ने किया है, जबकि कहानी, लेखन और निर्माण की जिम्मेदारी सागर बी. शिंदे ने संभाली है। 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' रासायनिक दुरुपयोग, खासकर खेती में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक तत्वों और उनके जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को केंद्र में रखती है। हाल ही में जारी पोस्टर इस गंभीर लेकिन बेहद अहम विषय की झलक देता है, जिसे फिल्म उजागर करने की कोशिश करेगी।

गौरतलब है कि यह कहानी केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। फिल्म औद्योगिक लापरवाही के छिपे खतरों और जागरूकता व जवाबदेही की तत्काल जरूरत को सामने लाने का प्रयास करती है। मेकर्स ने संकेत दिए हैं कि आने वाला टीज़र दर्शकों को 'द इंडिया स्टोरी' की गंभीर और प्रभावशाली दुनिया की एक गहरी झलक देगा, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ेगी। साथ ही पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे काजल अग्रवाल और तलपड़े से फिल्म में दमदार और भावनात्मक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

फिल्म को सह-निर्माता सुमित बागड़े, अनीता जाधव, विनायक सैदानी, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी का समर्थन मिला है। वहीं, सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकड़े, एडिटिंग आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आज़मी और साउंड डिज़ाइन अनमोल भावे का है। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज़ होगी। यह ज़ी स्टूडियोज़ की वर्ल्डवाइड रिलीज़ होगी।

नवकार महामंत्र में आत्मा के श्रेष्ठ गुणों की आराधना की गई है : आचार्य पार्श्वचंद्र

मंगल गीत व भक्ति संध्या आज, मोक्षमालारोपण कार्यक्रम कल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गणेशबाग में पंद्रह दिवसीय आत्म आराधना उपधान प्रथम सोपान साधना में शुक्रवार को श्रद्धालुओं को सम्बोधित करते हुए आचार्यश्री पार्श्वचंद्रजी ने कहा कि नवकार महामंत्र में गुणों को नमस्कार है। इसमें आत्मा के श्रेष्ठ गुणों की आराधना की गई है। व्यक्ति जब सच्चे भाव से परमेष्ठि का स्मरण करता है, तब उसके भीतर भी संयम, करुणा और वैराग्य के संस्कार जागृत होने लगते हैं।

उन्होंने नवकार महामंत्र के पाँचवें पद 'णमो लोए सव्वसाहूणं' की व्याख्या करते हुए कहा कि संसार के सभी साधु-साध्वियों को नमस्कार करना उनके गुणों के प्रति श्रद्धा और समर्पण प्रकट करना है। साधु वह है जिसने सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर आत्मकल्याण के मार्ग को अपनाया है। साधु स्वयं मोक्षमार्ग पर चलते हैं और सभी जीवों को भी मोक्षमार्ग की प्रेरणा देते हैं। ङ्कडॉ. पदमचंद्रमुनिजी ने कहा कि उपधान तप, मुनि जीवन को आत्मसात करने का एक श्रेष्ठ प्रयास है। उपधान के दौरान पूरे दिन में लगभग 150 वंदनाएँ होती हैं, जिससे साधक को अपूर्व उल्लास और आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। जब साधक श्रद्धा एवं विनयपूर्वक वंदना करता है, तब वह उच्च गोत्र कर्म का बंध करता है। उन्होंने कहा कि सामायिक आराधना का लाभ अत्यंत दुर्लभ और महान है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो पुण्य दस लाख गायों के दान से भी प्राप्त नहीं होता, वह शुद्ध सामायिक की आराधना से प्राप्त हो सकता है। उपधान तप करना, करवाना एवं उसकी अनुमोदना करना तीनों ही शुभ सामुदानिक कर्म के बंध के कारण बनते हैं। साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघ की सेवा में उत्कृष्ट भाव एवं रसायन प्रकट हो, तो तीर्थंकर नामकर्म के उपार्जन का महान अवसर प्राप्त होता है।

उन्होंने 'संयम बिना कोई मोक्ष जाने वाला नहीं' गीतिका का वर्णन करते हुए कहा कि यदि अभी संयम और धर्म आराधना की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो पंचम आरा के अंत तक अत्यंत विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी तथा जीव को छठे आरे में भी जन्म लेना पड़ सकता है, जहाँ चारों ओर केवल दुःख ही दुःख व्याप्त रहेगा। जयधुरंधरमुनिजी ने धर्म भावना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मा के कल्याण और मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए धर्मों का पालन करना जीवन का वास्तविक सार है।जयपुरंदरमुनिजी ने 14 नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मोन्नति के लिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए तथा अनावश्यक इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग कर संतोषमय जीवन अपनाना चाहिए। प्रातः समणी निदेशिका सुयशनिधि ने अणुप्पेहा ध्यान साधना का प्रशिक्षण दिया। उपधान तप के 80 आराधकों ने सामूहिक रूप से तेले के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। जयकलशमुनिजी एवं जयसुबोधमुनिजी ने आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत गीतिका प्रस्तुत की।ङ्कइस मौके पर गणेशबाग, हलसूरु संघ, मारथहल्ली संघ के सदस्य उपस्थित थे। उपधान तप आराधना में चंदनबाला महिला मंडल, मुनिरेड्डीपाल्यम की मंत्री अनिताबाई बोहरा के नेतृत्व में मंडल की सदस्याओं एवं श्रेयांस पारणा समिति के कोषाध्यक्ष महावीरचंद श्रीश्रीमाल, महावीरचंद लुंकड़, कोमल धोका, सुरेंद्र रांका एवं अजीत बाघमार की सेवाओं की सराहना की गई। प्रचार प्रसार प्रभारी जेके महावीरचंद चोरड़िया ने गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को प्रातः गणेशबाग में तपस्वियों की अनुमोदनार्थ मंगल गीत तथा शाम को ग्रैंड कैसल सभागार में वैराग्यवर्धक भक्ति संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें संगीतकार विक्की पारेख अपनी प्रस्तुति देंगे। आराधकों का मोक्षमालारोपण का कार्यक्रम 24 मई को होगा।

मंत्रों से भाग्य में परिवर्तन संभव है : साध्वीश्री पावनप्रभा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के बन्नरघट्टा रोड तेरापंथ सभा के तत्वावधान में एक श्रद्धालु के निवास पर साध्वीश्री पावनप्रभाजी, आत्मयशाजी, उन्नतयशाजी व रम्यप्रभाजी के सान्निध्य में गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र के अवसर पर पंच ऋषि अनुष्ठान का आयोजन हुआ जिसमें 150 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अनुष्ठान के दौरान श्रीमद जयाचार्य द्वारा रचित महामंगलकारी गीतिकाओं का विनोद कोठारी ने गान किया। इस मौके पर साध्वीश्री पावन प्रभाजी ने मंत्रों का जप करवाते हुए कहा कि यह अनुष्ठान सर्वसिद्धि प्रदायक, महामंगलकारी एवं कल्याणकारी है। इसके रचयिता श्रीमद जयाचार्यजी हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र व पंचमी के शुभ संयोग में यह अनुष्ठान करना वास्तव में सौभाग्य का प्रतीक है। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, मंत्रों से भाग्य में परिवर्तन संभव है। उपस्थित अन्य साध्वीवृन्दों विभिन्न मंत्रों का गान किया। इस मौके पर तेरापंथ समाज के अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। जितेन्द्र घोषल व विक्रम दुगड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया।

हर काल में होता है क्रांतिकारी विचारों का विरोध : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कंपली। शुक्रवार को मुनिसुव्रतस्वामी जैन श्वेतांबर संघ के तत्वावधान में हुंडिया भवन में आयोजित प्रवचन सभा को संबोधित करते हुए शुक्रवार को जैनाचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि जीते जी मनुष्य की या उसके क्रांतिकारी विचारों की बहुत कीमत नहीं होती। लोग रूढ़ियों और परंपरागत मान्यताओं में जकड़े होते हैं। उनका मन सत्य और नए विचारों को स्वीकार करने का साहस नहीं करता। दुनिया की यही रीत है कि वह उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके विचारों का मूल्यांकन करती है।क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी विचार कालजयी होते हैं, पर वे तत्कालीन समाज को हजम नहीं होते, इसलिए हर नई बात या नए व्यक्ति के संबंध में विरोध के सुर मुखर बनते हैं। यह समाज का दुर्भाग्य भी है और लोगों की अज्ञानता भी।ङ्कआचार्यश्री ने कहा कि समाज में बहुधा लोग झूठी शान-शौकत के लिए जीते हैं। नाम-सम्मान की उन्हें तीव्र भूख होती है। अहं का पोषण और स्वार्थपूर्ण चिंतन उनके जीवन का हिस्सा होता है। व्यक्तिगत हितों को वे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे लोगों को धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र या समाज के हितों की चिंता नहीं होती। उनके पास दूरगामी परिणामों का व्यापक चिंतन भी नहीं होता। यही कारण है कि हर काल में क्रांतिकारी एवं परिवर्तनकारी व्यक्तियों और विचारों का बहुत विरोध होता है। भगवान महावीर के जमाने में उनके 363 विरोधी संगठन थे। आचार्यश्री ने कहा कि झूठ से परे हटकर, स्वार्थ वृत्तियों को कम कर, वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा नए दृष्टिकोण से सोचने-समझने की जब क्षमता खड़ी होती है, तभी क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी विचारों से राष्ट्र एवं समाज लाभान्वित होते हैं।

सविता पारीक को मिला 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अचीवर' अवार्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली आरटी नगर निवासी सत्यनारायण जोशी (गुरुश्री सत्यज्वालाजी) की पुत्री सविता पारीक को 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डर्स अचीवर' अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

सविता को यह सम्मान वर्ष 2025 के 3 सितम्बर से वर्ष 2026 के 29 जनवरी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय में पांच पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया। इन पेटेंटों में 'फैक्शनल जीपीयू वर्क लोड का लाइव माइग्रेशन' तथा 'ट्रांसीवर के भीतर स्व-विनियमित थर्मल नियंत्रण' जैसे अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार शामिल हैं। ये अविष्कार एनवीलिंक, डेटासेंटर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसी उन्नत तकनीकी श्रेणियों से संबंधित है। 37 वर्षीय सविता पारीक मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की निवासी हैं और अपने अभिभावकों के साथ आरटी नगर में रह रही हैं। उनकी इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि गत बुधवार 20 अप्रैल को की गई और उन्हें रिकार्ड पत्र प्रदान किया गया।

ज्ञातव्य है कि सविता पारीक छह माह के अंतराल में एक ऑथर के रूप में पांच पेटेंट दर्ज कराने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। उनकी इस सफलता को भारत की तकनीकी प्रतिभा, नवाचार क्षमता और वैश्विक स्तर पर बढ़ती वैज्ञानिक भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

'जोश टॉक्स' पब्लिक स्पीकिंग कार्यशाला में 37 किशोर हुए ग्रेजुएट्स

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) साउथ लेडीज़ विंग द्वारा सक्षम पहल के अंतर्गत किशोरों के लिए छह दिवसीय व्यक्तित्व विकास एवं पब्लिक स्पीकिंग कार्यशाला 'जोश टॉक्स'का आयोजन किया जिसमें 37 किशोरों ने भाग लिया। चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने कहा, बच्चों को सिर्फ बोलना नहीं, अपनी बात निर्भय होकर रखना सीखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आज अपने विचारों को आवाज़ देना सीख जाते हैं, वही कल समाज का नेतृत्व करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल एवं स्वयं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कला विकसित करना था। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को डिबेट, रोल प्ले, स्टेज प्रेजेंटेशन, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, स्टोरी टेलिंग एवं विभिन्न इंटरैक्टिव सेशन्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। बुधवार को आयोजित समापन समारोह में सभी 37 प्रतिभागियों को टॉक्स ग्रेजुएट्स के रूप में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अनमोल जैन ने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास और परिपक्व सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों द्वारा चुने गए विषय और उनकी प्रस्तुति की सराहना की। फैकल्टी सदस्य अवधि चौहान एवं यश दुग्गड़ ने छह दिनों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बताया।

गाय आंदोलन से नहीं, अपितु गौपालन करने से बचेगी : राष्ट्रसंत कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गंगानगर जैन स्थानक में आयोजित प्रवचन सभा में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने कहा कि एक तरफ गाय को हम मां कह कर उसकी पूजा करते हैं, दूसरी ओर उसे प्लास्टिक थैली और गंदगी खाने को मजबूर करते हैं, गोचर भूमि पर कब्जा करते हैं, चमड़े की वस्तु काम में लेते हैं जिसके लिए हमें गहन चिन्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि गाय का मंदिर बनाने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं पर दूध न देने पर हम गाय को लावारिश छोड़ देते हैं, जो की पाप है। हम सभी को गोवंश का पालन करना होगा, तभी गाय कटने को नहीं जाएगी। गाय आंदोलन से नहीं पालन करने से ही बचेगी।ङ्क संतश्री ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार मछली मंत्रालय बना सकती है तो गौ मंत्रालय क्यों नहीं बना रही?

पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है। गौहत्या के लिए किसी कौम विशेष को दोषी ठहराना सरासर गलत है। गौहत्या के हम सब जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्य है भगवान कृष्ण और महावीर का देश विश्व में दूसरे नंबर पर गौ मांस निर्यातक के रूप में बदनाम हो रहा है जो कि सरकार के लिए कलंक की बात है। संतश्री ने बताया कि आज हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार को भी चाहिए कि जन भावना का सम्मान करते हुए गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दे। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरचंद गुंदेचा, सुनील नंदावत, जसवंत गन्ना, रितेश पामेचा, रूपचंद लोढ़ा, देवराज बोहरा, मनोज नंदावत, मनीष दक,अशोक पोखरना, महिला मंडल से मीना पितलिया, गुणमाला जैन, नगीना गन्ना आदि ने संतों का स्वागत किया।

इंद्रियों को वश में करने का एकमात्र रहस्य है 'मन पर लगाम' लगाना : डॉ. समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के हीराबाग जैन स्थानक में विराजित डॉ. समकितमुनिजी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए 'मन की गुलामी' और 'इंद्रियों के भटकाव' पर विषय पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि आज का इंसान चाँद-तारों तक पहुँच गया, उसने पूरी दुनिया की सुख-सुविधाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन विडंबना देखिए कि जो इंसान पूरी दुनिया को जीतने का दावा करता है, वह अपने ही भीतर बैठे एक छोटे से 'मन' से हारकर बैठा है। जब तक यह मन वासनाओं, इच्छाओं और लोभ का गुलाम है, तब तक बाहर तुम चाहे कितने भी बड़े सेठ या सिकंदर बन जाओ, भीतर से तुम एक 'कंगाल' ही रहोगे। ङ्कङ्कमुनिश्री ने इंसान की भटकान का मूल कारण बताते हुए कहा कि लोग अपनी आँखों, कानों और जुबान को वश में करने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब तक 'मन' वश में नहीं है, तब तक यह सब व्यर्थ है।

हमारी पांचों इंद्रियां केवल घोड़े हैं और इन घोड़ों को चलाने वाला असली सारथी हमारा 'मन' है। यदि तुमने केवल इस एक मन को साध लिया, इस पर नियंत्रण कर लिया, तो पांचों इंद्रियां और उनके विकार स्वतः ही तुम्हारे वश में आ जाएंगे। बिना मन को साधे, इंद्रियों को रोकना रेत की दीवार बनाने जैसा है, जो एक झटके में ढह जाती है। ङ्कङ्कमनुष्य के कर्म सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म रहस्य उद्घाटित करते हुए मुनिश्री ने कहा, हम सोचते हैं कि हम शरीर से पाप करते हैं, लेकिन सच यह है कि शरीर तो केवल एक कठपुतली है। कोई भी पाप या पुण्य शरीर से होने से पहले इस 'मन' के भीतर जन्म लेता है। मन ही वह असली फैक्टरी है जहाँ हमारे विचार बनते हैं। यदि मन में मलिनता है, तो इंसान तीर्थ में बैठकर भी घोर पाप का बंध कर लेता है और यदि मन शुद्ध है, तो इंसान घर में बैठकर भी 'पुण्य' की सर्वोच्च शिखर को छू लेता है। संतश्री ने एक अचूक चेतावनी दी कि यह मन एक ऐसी दोधारी तलवार है जो इंसान की गति तय करती है। यदि इस मन को खुला छोड़ दिया, तो यह तुम्हें वासनाओं के ऐसे दलदल में धकेलेगा जिसकी मंजिल केवल 'दुर्गति' है। लेकिन यदि इसी मन पर वैराग्य और ज्ञान का अंकुश लगा दिया, तो यही मन तुम्हें 'सद्गति' के सिंहासन पर बैठा देगा। हीराबाग संघ के अध्यक्ष डॉ भीकमचंद सकलेचा ने सभी को धन्यवाद दिया। मंत्री अशोक बांठिया ने इस कार्यक्रम में मुनिश्री के आगामी कार्यक्रमों व चातुर्मास प्रवेश की जानकारी दी।

प्रतियोगिता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कर्नाटक आर्य वैश्य महासभा द्वारा बेंगलूरु के वैश्य हॉस्टल गांधीनगर में शुक्रवार को विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता 'वेल्लोर-2026' का आयोजन किया गया जिसमें छात्रावास के विद्यार्थियों ने कैरम, टेबल टेनिस, ट्रेजर हंट, चैस, आईपीएल ऑक्शन एवं अन्य रचनात्मक स्पर्धाओं में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महेंद्र मुणोत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमें खेल को खेल भावना से ही खेलना चाहिए, जीत-हार से ज्यादा प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक होता है ।

बेंगलूरु पुलिस ने टाउन हॉल में प्रदर्शन के 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आह्वान पर लोगों को चेताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु पुलिस ने शुक्रवार को लोगों को 24 मई को टाउन हॉल के पास कथित तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटक नामक एक समूह द्वारा आयोजित प्रस्तावित शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला कार्यक्रम में भाग लेने या सोशल मीडिया पर इससे संबंधित संदेशों को प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। बेंगलूरु सिटी पुलिस ने एक प्रेस नोट में कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लोगों को रविवार को टाउन हॉल के सामने बड़ी संख्या में एकत्र होकर शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल ने इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है और न ही पुलिस या जीबीए अधिकारियों द्वारा स्थल के उपयोग की मंजूरी दी गई है। पुलिस ने कहा, यह जानकारी सामने आई है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी, कर्नाटक' शीर्षक से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित की गई है, जिसमें 24 मई को टाउन हॉल के सामने शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में एकत्र होने का निमंत्रण दिया गया है।

पुलिस बयान के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक अगस्त 2022 के आदेश के मुताबिक फ्रीडम पार्क के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन, धरना और रैलियों की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए टाउन हॉल के सामने किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाना न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

कर्नाटक 'एपिस सेराना' मधुमक्खी को राज्य कीट और मालाबार वृक्ष मेंढक को राज्य उभयचर घोषित करेगा

बेंगलूरु। कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने शुक्रवार को कहा कि मधुमक्खी 'एपिस सेराना' को राज्य कीट और मालाबार वृक्ष मेंढक को राज्य उभयचर के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित करने की प्रक्रिया जारी है। जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कई देश जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर जोर देने के लिए पक्षियों, पशुओं और पेड़ों जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा करते हैं।

विल्सनगार्डन जैन युवा संगठन ने सेवा सहयोगी मकाणा परिवार का सम्मान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु । शहर के विल्सन गार्डन जैन युवा संगठन के तत्वावधान में 50वां मानव सेवा कार्यक्रम चिन्नयनपाल्या स्थित आंजनैया स्वामी मंदिर के समीप आयोजित किया गया। अध्यक्ष जितेश वया ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि संगठन द्वारा प्रतिमाह मानव सेवा कार्य जैसे अन्नदान, विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री सहयोग, बैग वितरण, अनाथाश्रम में राशन वितरण कार्यक्रम आदि किए जा रहे हैं। संगठन द्वारा मानव सेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 25 कार्यक्रमों में मुख्य लाभार्थी मीठालाल-उगमादेवी मकाणा परिवार का सम्मान किया गया। मीठालाल मकाणा ने कहा कि मानव सेवा के कार्यों से आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर विल्सनगार्डन संघ के अध्यक्ष नेमीचंद भंसाली, मंत्री जंबूकुमार मकाणा सहित युवा संगठन व प्रेरणा बहु मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**